04 - विश्व की भलाई में भारतीय विरासत का वैशिष्ट्य

05 - कारगिल फतह : भारत माता के माथे पर शौर्य का टीका

A Daily News Magazine

इंदौर

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024

06 - ख्वाब थे चमचमाती सड़क के यहां कीचड़ से लथपथ होकर करना पड़ रहा सफर

07- राजस्व महा अभियान 2.0, 31 अगस्त तक जारी है, इसका लाभ...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 275, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

जो बाहर हैं राजसत्ता से
वे विरोधी नहीं हैं उसके
उन्हें तो आकांक्षा है उसी की
उनका विरोध राजसत्ता का विकल्प नहीं
जो भीतर हैं राजसत्ता के
वे आलोचक नहीं हैं उसके
उन्हें तो सदैव आकांक्षा है उसी की
उनकी सत्ता सबकी सत्ता का विकल्प नहीं
जो अनजान हैं दरिद्रता से
वे द्रवित हैं इस तरह उस पर
उनकी आकांक्षा है उसे बनाये रखने की
उनका द्रवित होना दरिद्रता का विकल्प नहीं
जो दूर हैं वैभव से
वे ललचाते हैं उसी पर
उनकी आकांक्षा है उसे पाने की
पर वैभव तो लालच का विकल्प नहीं
जो भागते फिरते हैं संसार से
वे रीझते रहते हैं उसी पर
कभी नहीं जा पाये उससे बाहर
उदासीनता संसार का विकल्प नहीं
नहीं मिलता विकल्प
उदासीनता और महत्वाकांक्षा से
नहीं मिलता ईर्ष्या से, डाह से
नहीं मिलता केवल विरोध से
मिलेगा वह जीवन के शोध से
जहां शामिल हों सब
परस्पर आश्रय में निर्भय
बस यही है विकल्प।

- ध्रुव शुक्ल

प्रसंगवश

भारत पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांके

जनरल मनोज नरवणे (रि)

यूनाइटेड सर्विस इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत-अमेरिका रक्षा संबंध के मसले पर हाल में दिल्ली में हुए एक सम्मेलन किया, जिसमें भाषण देते हुए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेट्टी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की तारीफ की मगर साथ में असंतोष पैदा करने वाला यह बयान भी दे दिया कि 'समय जब संघर्ष का हो तब रणनीतिक स्वायत्तता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती।'

जाहिर है, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा थी, जिस पर यूक्रेन समेत कुछ यूरोपीय देशों ने सख्त टिप्पणी की थी। गार्सेट्टी ने रूस-यूक्रेन युद्ध की तुलना चीन-भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बने हालात से की और कहा कि 'हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं' इसलिए 'अब किसी भी युद्ध से हम अछूते नहीं रह सकते।' इससे ये दो महत्वपूर्ण पहलू उभरते हैं– 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'युद्ध या लड़ाई।'

रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा का संबंध खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर फैसले करने की किसी देश की क्षमता से होता है। भारत-अमेरिका संबंधों के मामले में रणनीतिक स्वायत्तता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर तब जब कोई लड़ाई चल रही हो या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया हो। रणनीतिक स्वायत्तता कई कारणों से भारत के हित में है, यह भारत-अमेरिका संबंध के संदर्भ में कभीकभार चुनौती प्रस्तुत कर सकती है लेकिन आम तौर पर इससे इस रिश्ते को चोट नहीं पहुंचती। रणनीतिक स्वायत्तता भू-राजनीति के व्यापक संदर्भ में भारत के लिए किस तरह फायदेमंद है, इस पर हम यहां बारीकी से विचार कर रहे हैं।

भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: भारत शुरू से, खासकर शीतयुद्ध वाले दौर में, गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। यह रवैया खेमेबंदी की राजनीति और महाशक्तियों के दांवपेच से मुक्त रहने की नीति से उपजा। युक्रेन युद्ध इसी दांवपेच का खेल है जिसमें 'नाटो' की साझी ताकत और रूस एक-दूसरे से भिड़े हुए हैं।

मौजूदा भू-रणनीतिक वास्तविकताएं : आज जो भू-राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका समेत कई देशों के साथ साझीदारी और गठबंधन करता रहा है। यह संतुलन भारत को अपने हित को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय साझीदारों के साझा लक्ष्यों के लिए सहयोग देने का मौका प्रदान करता है।

भारत-अमेरिका संबंध: भारत और अमेरिका के रिश्ते में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इसके पीछे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर साझा सरोकारों का हाथ रहा है। लेकिन फैसले करने के मामले में भारत ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी है, खासकर रक्षा सामग्री की खरीद, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति, और कूटनीतिक संबंधों के बारे फैसले करने में।

युद्ध के प्रभाव : युद्ध या तनाव में वृद्धि के दौरान रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर भारत का रुख खासतौर से प्रासंगिक हो जाता है। वह अमेरिका और दूसरे देशों के साथ अपनी साझीदारी को तवज्जो तो देता है लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक आकलनों के आधार पर स्वतंत्र फैसले करने के अपने संप्रभु अधिकार को प्राथमिकता देता है।

मतभेदों का निपटारा: करीबी संबंध के बावजूद भारत और अमेरिका कुछ वैश्विक मसलों या क्षेत्रीय संघर्षों के बारे में अलग-अलग नजरिया रखते हैं। उदाहरण के लिए, रूस के साथ भारत का प्राचीन रक्षा संबंध। रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसे कई सहयोगी देशों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए इन मतभेदों का निबटारा करने की गुंजाइश बनाती है।

नजरिया: रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा ही भविष्य में भारत-अमेरिका संबंधों को स्वरूप प्रदान करती रहेगी। दोनों देश प्रतिरक्षा, आर्थिक तथा तकनीकी मामलों में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाते हुए संप्रभुता के मामले में आपसी सम्मान और अपने रणनीतिक समीकरणों में स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हैं। कभी-कभार अड़चनें पैदा हो सकती हैं लेकिन उन्हें आपसी सम्मान की भावना से बर्दाश्त किया जा सकता है।

सहयोग के क्षेत्र : भारत और अमेरिका प्रतिरक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद के विरोध, व्यापार तथा निवेश, टेक्नोलॉजी, और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में विस्तृत सहयोग करते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए अमेरिका के साथ गहरे संबंध बनाने की छूट देती है।

चुनौतियां और मतभेद: भारत और अमेरिका के रिश्ते में कभीकभार चुनौतियां और मतभेद उभरते रहते हैं, मसलन कुछ वैश्विक मसलों को लेकर उनके विचारों में भिन्नता होती है या रूस के साथ भारत के रक्षा संबंधों को ही लें। लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता भारत को अपने मूल हितों पर कोई समझौता किए बिना इन मतभेदों को निबटाने की गुंजाइश बनाती है।

द्विपक्षीय समझौते: दोनों देशों ने ऐसे प्रमुख समझौते किए हैं जिनमें भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की बात शामिल है। ये समझौते आंतरिक कार्रवाई को मजबूत बनाते हैं और एक ऐसी अहम क्षेत्रीय ताकत के रूप में भारत की भूमिका को मान्यता देते हैं जिसकी अपनी रणनीतिक जरूरतें हैं।

संघर्ष का मतलब व्यक्तियों, समूहों, या देशों के बीच मतभेद, विरोध या तनाव है। इसके अंतर्गत कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, या भूमि संबंधी विवादों को भी शामिल किया जा सकता है। ये मामूली विवादों से लेकर छिटपुट झड़पों या गंभी टकरावों के रूप में हो सकते हैं जिनमें हिंसा और सशस्त्र मुक़ाबले के रूप में भी हो सकते हैं। संघर्ष स्थानीय हो सकते हैं, विशेष मसलों या क्षेत्रों को लेकर। इसके विपरीत, युद्ध खास तरह का संघर्ष होता है जो देशों या बड़े सशस्त्र समूहों के बीच संगठित और लंबी सशस्त्र लड़ाई के रूप में होता है। युद्ध में अक्सर एक या ज्यादा पक्षों की ओर से दुश्मनी का औपचारिक ऐलान किया जाता है, जिसके बाद बाकायदा युद्ध शुरू होता है। इस नजरिए से इजरायल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, जबकि यूक्रेन में जो कार्रवाई चल रही है उसे युद्ध जैसी स्थिति कहा जा सकता है। अगर किसी संघर्ष या युद्ध से हमारे मूल हित प्रभावित होते हैं तो हमें उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। वरना किसी को हम पर ऐसे किसी युद्ध में शामिल होने का दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो हमारे मतलब का नहीं है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस बयान के पीछे यही मंशा थी कि 'यूरोप (पश्चिम) को अपनी इस मानसिकता को छोड़ना होगा कि उसकी समस्याएं सारी दुनिया की समस्याएं हैं, कि दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

खनिज पर टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-

खनिजों पर लगने वाला टैक्स नहीं माना जा सकता रॉयल्टी

केंद्र सरकार को लगा तगड़ा झटका, राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खनिज पर टैक्स को लेकर चले आ रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने 8-1 के बहुमत से यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। अलग-

अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं पहुंची थीं। इसमें कोर्ट को यह तय करना था कि मिनरल्स पर रॉयल्टी और खदानों पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्य सरकार को होने चाहिए या नहीं। इस मामले को लेकर 8 दिन तक सुनवाई चली।

9 जजों की संवैधानिक बेंच ने 8-1 से सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है। इस बेंच में 9 जजों की बेंच में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज शामिल थे। इनमें 8 जजों ने एकमत से फैसला सुनाया है, नागरत्ना ने अलग।

इंतजार खत्म! जारी हुई यूपी पुलिस परीक्षा की नई तारीख

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया। परीक्षा अगस्त में 5 दिन– 23 से 31 अगस्त तक होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। हर दिन दो शिफ्ट में एग्जाम होंगे। यानी 10 शिफ्ट में पूरी

परीक्षा। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी।

कोर्ट का फैसला

वेबसाइट से हटवाने लगे तो होंगे गंभीर परिणाम

- **सीजेआई डीवाय चंद्रचूड़ ने रोका मद्रास हाईकोर्ट का आदेश**

नई दिल्ली (एजेंसी)। जब कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो वह सबके लिए उपलब्ध दस्तावेज (पब्लिक रिकॉर्ड) का हिस्सा हो जाता है। यह मानते हुए कि आरोपी बरी हो गया, उसे लेकर दिए गए फैसले को किसी वेबसाइट से हटाए जाने का आदेश हाईकोर्ट कैसे दे सकता है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (सीजेआई चंद्रचूड़) ने एक फैसले पर रोक लगाते हुए पूछा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कानूनी खबरें देने वाले एक पोर्टल से उस फैसले को अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए कहा गया था, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले में बरी कर दिया गया था। सीजेआई ने कहा, निर्णय सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और अदालतों द्वारा उन्हें हटाने के आदेश के गंभीर प्रभाव होंगे। पीठ के फैसले से एक व्यक्ति बरी हो गया है।

लटकाइए-अटकाइए मत सीट बंटवारा कर दीजिए

- **अमित शाह से बोले अजित पवार, देर रात की मुलाकात**

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। दोनों पक्षों की ओर से इस पर चुप्पी ही रखी गई है, लेकिन कयास हैं कि मीटिंग सीट बंटवारे को लेकर थी। चर्चा है कि अजित पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 80 से 90 विधानसभा सीटों की मांग की है। खासतौर पर उन 54 सीटों पर अजित पवार ने दावेदारी की, जिन पर संयुक्त एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। अजित पवार गुट के खिलाफ आरएसएस के कई विचारकों ने आवाज उठाई थी। लोकसभा नतीजों के बाद पांचजन्य में एक लेख लिखा गया था, जिसमें अजित पवार से गठबंधन को बैकफायर करने वाला फैसला बताया गया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में भी इस पर सवाल उठाए गए थे।

7 दिन बाद देश के सामने आए अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन

- **उम्मीदवारी छोड़ने पर कहा-नई पीढ़ी को मशाल सौंपी, भावुक बेटी ने गले लगाया**

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना महामारी से ठीक होकर 7 दिन बुधवार को देश के सामने आए। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर ओवल ऑफिस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं नई पीढ़ी को मशाल सौंपना चाहता हूं। बाइडेन का ये ओवल ऑफिस से यह चौथा संबोधन था। बुधवार को उनके एड्रेस के दौरान पत्नी जिल बाइडेन, बेटी ऐशले बाइडेन, बेटा हंटर बाइडेन समेत बाइडेन के नाती-पोते भी वहां मौजूद रहे। बाइडेन की सीट के पीछे भी परिवार के साथ उनकी अलग-अलग तस्वीरें रखी हुई थीं। अपनी 11 मिनट की स्पीच के दौरान बाइडेन ने अमेरिका की राजनीति में उतरने और शिखर तक पहुंचने के बारे में बात की। उनके स्पीच के दौरान पत्नी समेत पूरा परिवार भावुक हो गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोयम्बटूर में 'एमपी इंटरएक्टिव सत्र' का दीप जला कर शुभारंभ किया

कोयम्बटूर में इन्वेस्ट एमपी इंटरएक्टिव सत्र शुरू

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोयंबटूर में आयोजित 'इन्वेस्ट एमपी-इंटरएक्टिव सत्र' का दीप प्रज्वलित कर तथा तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर शुभारंभ किया। सीएम ने सेशन को संबोधित करने की शुरुआत 'एल्लोरुक्कुम वणक्कम' बोलकर की

- **सीएम तमिल में बोले– एल्लोरुक्कुम वणक्कम, तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर अभिवादन किया**

और मौजूद सभी अतिथियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के उद्योगपतियों और उद्यमियों को मध्यप्रदेश से जोड़ने के लिए एमपी सरकार का एक उद्योग कार्यालय कोयम्बटूर में खोला जाएगा। यह कार्यालय एमपी और तमिलनाडु के बीच कारोबार, व्यापार बढ़ाने के लिए सेतु बनने का काम करेगा।

सीएम ने कहा- मध्यप्रदेश में मौजूद संसाधनों के उपयोग के लिए वे कोयम्बटूर में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने आए हैं। हम और आप मिलकर देश को दुनिया का नंबर वन कंट्री बनाने का संकल्प लें।

एमपी का रिश्ता मजबूत बनाने आए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तमिलनाडु और एमपी का रिश्ता मजबूत बनाने के लिए आए हैं। यहां से कुछ छीनने नहीं बल्कि नए अवसर देने के लिए आए हैं ताकि और अधिक डेवलपमेंट हो सके। यहां के उद्यमियों को जुड़ने के लिए एमपी का एक उद्योग कार्यालय कोयम्बटूर में खोलने का निर्णय किया है। यहां का कार्यालय एमपी तमिलनाडु के बीच कारोबार व्यापार बढ़ाने के लिए सेतु बनने का काम करेगा।

इलैया राजा टी. ने किया अनुवाद

इस सेशन में तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी और एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी इलैया राजा टी ने सीएम मोहन यादव की बात को बात तमिलनाडु के निवेशकों तक पहुंचाने का काम किया। सीएम यादव के संबोधन के दौरान सीएम जब दो वाक्यों में अपनी बात कहते तो इलैया राजा तमिल भाषा में उनकी बात को कोयम्बटूर के सेशन में पहुंचे उद्योगपतियों को तमिल भाषा में अनुवाद कर बताने का काम करते रहे। इस तरह सीएम ने दस मिनट तक अपना संबोधन दिया।

अब स्वदेशी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा डीआरडीओ

रूस के एस-400 को देगा टक्कर, स्टेज-2 का परीक्षण भी हुआ सफल

नई दिल्ली (एजेंसी)। अब भारत को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के एम-400 पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (डीआरडीओ) सिस्टम तैयार कर रहा है। इस दिशा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। ओडिशा के चांदीपुर के एलसी-धामरा से इस सिस्टम के दूसरे चरण का सफल ट्रायल किया गया। खास बात यह है कि यह बैलेस्टिक मिसाइल दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से निपटने में सक्षम है। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रायल के दौरान इस सिस्टम ने हवा में डमी के तौर पर तैनात दुश्मन के मिसाइल को भी काफी सटीकता से टारगेट किया। यह मिसाइल ना सिर्फ जमीन बल्कि हवा से भी आने वाले किसी भी टारगेट

को खत्म करने में सक्षम है। ट्रायल के दूसरे चरण में एडी (एडवांस्ड एरिया डिफेंस) एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक ही नष्ट कर देगी। यह सिस्टम हवा में 100 किमी से कम ऊंचाई वाले किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। लॉन्च पैड श्री से पहले पृथ्वी-2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल एल-1 की लॉन्चिंग की गई। इसमें लंबी दूरी के सेंसर, कम विलंबता संचार प्रणाली और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों से युक्त एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली लगाई गई है।

सुबह सवेरे
इंदौर ■ शुक्रवार, 26 जुलाई 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पेरिस ओलंपिक से देश के लिए आ गई पहली खुशखबरी

- महिला तीरंदाजों का भौकाल, टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में मारी एंट्री
- अंकिता की सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस, कोरिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, नंबर-1 पर

पेरिस (एजेंसी)। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 से पहली खुशखबरी भेजी है। टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की तीनों तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। भारत ने चौथा स्थान हासिल किया, जिससे महिला टीम वर्ग में मुख्य तीरंदाजी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया। अंकिता भक्त के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तीरंदाजी पदक की तलाश में अपनी राह थोड़ी आसान कर ली है। अपने पहले ओलंपिक में अंकिता भक्त ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। वह महिला व्यक्तिगत स्पर्धा से पहले 11वीं वरीयता प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने 666 स्कोर बनाया, जो उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। साथ ही 18 वर्षीय भजन कौर 22वीं वरीयता (659 स्कोर) पर रहीं, जबकि अनुभवी दीपिका कुमारी 23वीं वरीयता (658 स्कोर) पर रहीं। अगर भारत महिला टीम में अपना क्वार्टर फाइनल

जीत जाती है तो तो उसका सामना मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया से हो सकता है। माना जा रहा है कि फ्रांस या नीदरलैंड्स से क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत हो सकती है। हालांकि, असली टक्कर सेमीफाइनल में होगी। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसकी भिड़ंत साउथ कोरिया से होगी। दक्षिण कोरिया ने ओलिंपिक इतिहास में तीरंदाजी में 27 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो किसी भी अन्य देश से 13 अधिक है।

संक्षिप्त समाचार

जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट से फिर लगा झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े करप्शन के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके अलावा अदालत ने शराब नीति से जुड़े

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि 25 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की हिरासत खत्म हो रही थी। सीबीआई ने 55 वर्षीय आप नेता को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उनकी पेशी तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

बीजेपी के सामने सीएम नीतिश कुमार ने कर दिया सरेंडर

पटना (एजेंसी)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने पटना में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट निराशाजनक रहा। केंद्र की ओर से बिहार को बजाने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया गया है। नीतिश कुमार फेल हो गए

हैं। उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। लालू यादव की सोमवार को तबीयत बिगड़ी थी। यूरिन में परेशानी के बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनके करीबियों ने कहा कि वे रुटीन चेकअप के लिए आए हैं। चेकअप में दो दिनों को समय लगता है। लालू दो दिनों से एम्स में थे। वहां से ठीक होने के बाद आज गुरुवार को पटना लौटे हैं।

राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल बना अब गणतंत्र मंडप

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का अब नाम बदल गया है। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। वहीं अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है।

सचिवालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति भवन देश का प्रतीक है और समृद्ध विरासत का संकेत देता है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से कहा गया, लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन तक लोगों की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन की पहचान को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और भावनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।

म.प्र.के कर्मचारियों को मिलेगा 1240 से 16000 तक एरियर

7.50 लाख खातों में रक्षाबंधन से पहले जमा होगी पहली किस्त; 2 किस्तें और मिलेंगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर की पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। केसवाइज स्टडी करने की जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग को दी गई है। पहली किस्त में 2 महीने के एरियर मिलेगा।

मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 प्रतिशत डीए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में दिया था। उसी समय वित्त विभाग ने कहा था कि महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिया जा रहा है।

जो विभाग आदेश देरी से जारी होने के कारण मार्च 2024 में 4 प्रतिशत डीए नहीं जोड़ पाए थे, वे अब हर महीने तीन महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डालेंगे।

श्रेणी के मुताबिक 620 से 8000 रुपए तक का फायदा

जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के मुताबिक 620 रुपए से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से देखें तो जुलाई में दो महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारियों के बैंक खातों में 1240 से 16 हजार रुपए तक आएंगे। तीन महीने का एरियर मिलने पर 1860 से 24 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे। एरियर की राशि सैलरी से अलग कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली जाएगी।

साल में दो बार बढ़ाया जाता है डीए

कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है। तय प्रक्रिया के तहत एक जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 या 4 प्रतिशत बढ़ना है। यह घोषणा जल्द होने की संभावना है।ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी।

ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद 4 महिलाओं की मौत

दमोह में परिजन बोले–अस्पताल की लापरवाही ने दुधमुंहे बच्चों से मां का आंचल छीना

दमोह (नप्र)। दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को प्रसव कराने पहुंचीं 4 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें से 2 ने बच्चों को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया। वहीं, 2 की मौत इलाज के दौरान जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 20 दिन बाद हुई। चारों की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी। परिवारवालों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने दुधमुंहे बच्चों से मां का आंचल छीन लिया।

अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई। शिकायत के बाद 2 टीमें गठित कर जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई। अब एक बार फिर जांच कराने के आदेश दिए गए हैं।

पेट में दर्ज हुआ और चंद मिनट में मौत हो गई– दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थीं। जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थीं। रात होते-होते कहा गया कि सीजर होगा। सब ठीक से हो गया। शिशु भी स्वस्थ था। कुछ देर बाद लक्ष्मी को पेट में तेज दर्द हुआ और चंद मिनट में लक्ष्मी की सांसें थम गईं।

डिलीवरी के बाद अगली सुबह नहीं देख सकी– दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना कोरी को भी पहला प्रसव हुआ, पर चंद घंटे में ही उनकी तबीयत बिगड़ी। दमोह जिला अस्पताल में आईसीयू में रखा गया, लेकिन संघर्ष ज्यादा नहीं चल सका और हर्षना अगली सुबह नहीं देख पाई।

परिजन को बताया किडनी फेल हो गई– दमोह के ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन ने सीजर से पहले बच्चे को जन्म दिया। परिवार अस्पताल में लोगों का मुंह मीठा करवाने लगा। कुछ घंटों बाद पता चला कि निशा की यूरिन पास होना बंद हो गई। परिजन को बताया गया किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में निशा को जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डायलिसिस कराया गया। 18 दिन संघर्ष के बाद निशा ने दम तोड़ दिया।

जबलपुर रेफर किया, वहां मौत हो गई– दमोह के ही हटा की हुमा का भी पहला प्रसव था। सीजर तक सब ठीक था, लेकिन उन्हें भी सीजर के बाद यूरिन पास होना बंद हो गई। उन्हें भी बताया गया कि किडनी फेल हो गई गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डायलिसिस हुआ, लेकिन 20 दिन के संघर्ष के बाद हुमा ने दम तोड़ दिया।

पति बोला– लापरवाही ने ही मेरी पत्नी की जान ली

जिन महिलाओं की सीजर से डिलीवरी कराई गई, उन सभी को यूरिन इंफेक्शन की शिकायत बताई गई, जबकि पहले हुई जांचों में इस तरह की कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी। सचिन चौरसिया ने बताया कि 4 जुलाई को पत्नी लक्ष्मी को जिला अस्पताल लेकर आए थे। वो पूरी तरह से ठीक थी। डॉक्टर ने कहा- ऑपरेशन होगा। सीजर से बच्चा हुआ। 3 घंटे बाद अचानक दर्द उठा और लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। लापरवाही ने ही मेरी पत्नी की जान ली है।

सीजर के कुछ घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ी

इकबाल खान ने बताया कि मेरी भतीजा बहू हुमा पति नईम को डिलीवरी के लिए 2 जुलाई को हटा अस्पताल लेकर गए थे, जहां से उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 4 जुलाई की रात सीजर से बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद हुमा की तबीयत बिगड़ गई। 5 तारीख की सुबह उसे जबलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कारण पूछा तो बताया गया कि यूरिन पास नहीं हो रही है। हुमा मेडिकल कॉलेज में 4 दिन आईसीयू में भर्ती रही। 8 डायलिसिस भी हुई, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 20 दिन बाद 24 जुलाई को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही उसने दम तोड़ दिया।

परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

नवजातों के सिर से मां का आंचल छिन गया है। परिवार के लोग दुखी हैं। अस्पताल प्रबंधन पर आक्रोशित भी हैं। उनकी मांग है कि प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को हटा में महिला के परिजन और समाज के अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हंगामा बरपा तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सप्ताह में मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

मेपकास्ट में डिफेन्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना हेतु नेवी के रियर एडमिरल और उनकी टीम की विजिट

नौसेना के लिए विकसित की जाएगी प्रौद्योगिकी

भोपाल। नौसेना (नेवी) के रियर एडमिरल इकबाल सिंह ग्रेवाल एवं उनकी टीम ने मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) में विजिट किया। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य मेपकास्ट के माध्यम से डिफेन्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना था। इस दौरान मेपकास्ट ने इस विंग की स्थापना के लिए अपना प्रस्तुतिकरण दिया। मेपकास्ट के वैज्ञानिकों, सलाहकारों एवं नौसेना के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान संयुक्त रूप से किये जाने वाले कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इन क्षेत्रों को लेकर डिफेन्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना मेपकास्ट में की जाएगी।

ए आई, मशीन लर्निंग लैब
सॉफ्टवेर आधारित तकनीकी
रोबोटिक्स
हाई एलटीटयूड ड्रोन
स्टार्ट अप एवं इन्क्यूबेशन

डाटा सिक्यूरिटी
रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब
टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम
इंडस्ट्री इंगेजमेंट प्रोग्राम
कोलेबोरेशन प्रोग्राम

इस विंग से रक्षा नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों एवं सेना के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। इस अवसर पर मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि मेपकास्ट में डिफेन्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विंग की स्थापना से स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान विनिमय को सुविधाजनक बनाते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और प्रतिभा विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा। विदित है कि इससे पूर्व मेपकास्ट द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेना के साथ एक इन्क्यूबेशन सेंटर भी खोला जा चूका है।नौसेना के अधिकारियों ने परिषद की जी आई एस लैब का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर मेपकास्ट के वैज्ञानिक, सलाहकार एवं नौसेना के अधिकारी उपस्थित थे।

संगीत मंथन

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय 26 और 27 जुलाई को आयोजित करेगा दो दिवसीय संगीत कार्यशाला

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगौर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा 26 एवं 27 जुलाई को मानविकी एवं उदार कला संकाय तथा टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के सौजन्य से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 'संगीत मंथन' विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में देश की विभिन्न संगीत की शैक्षणिक संस्थाओं के विशेषज्ञ शिरकत करेगें। कार्यशाला का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डॉ भरत शरण सिंह, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल, विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष श्री अशोक कड़ेल, अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे करेंगे। कार्यशाला में प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार उमाकांत गुंदेचा, वरिष्ठ संगीत मनीषी पं. किरण देशपांडे, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलगुरु प्रो. रमेश चंद्र भारद्वाज, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरु प्रो. साहित्य कुमार नाहर, प्रो. धीरेंद्र शुक्ला, ओएसडी उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न सत्रों में उद्बोधन देंगे। विश्वविद्यालय की प्रो चांसलर डॉ अदिति चतुर्वेदी वत्स, प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. अमिताभ सक्सेना, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह और टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक श्री विनय उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्राध्यापक तथा शोधार्थी भी अपना शोधपत्र वाचन करेगें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आवंटित विषय संगीत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों का परीक्षण करना तथा नवीन सुझाव प्रस्तावित करते हुए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा और उप विषय पर भारतीय ज्ञान के इतिहास का समावेश करना है। इस कार्यशाला में परम्परा, विकास, इतिहास, आधुनिक एवं तकनीकी प्रभाव के साथ विभिन्न विषयों, कलाओं के साथ संगीत के अन्तर्सम्बन्ध–सहसंबंध तथा सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सरोकारों पर भी विचार मंथन होगा।

उन्होंने बताया कि रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा इस कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दी जावेगी।

नीट-खेडकर विवाद के बीच यूपीएससी ने उठाया बड़ा कदम

बदल दिया एग्जाम पैटर्न, अब न्यू टेक्नोलॉजी का करेगा इस्तेमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट यूजी 2024 और दिव्यांगता कोटे के तहत चयनित विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर विवाद के बीच संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बड़ी जानकारी दी है। यूपीएससी अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने जा रहा है। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए यूपीएससी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इसमें आधार फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-आधारित सीसीटीवी निगरानी शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह योजना बनाई है। यह खबर ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले के बीच सामने आया है, जो सिविल सेवा परीक्षा में अपनी पहचान फर्जी करने के लिए यूपीएससी जांच का सामना कर रही हैं।

यूपीएससी की यह योजना नीट-यूजी परीक्षा सहित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के परीक्षा कराने के तरीकों पर सवाल खड़े होने के बाद आई है। जानकारी के अनुसार, यूपीएससी परीक्षाओं के दौरान टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए पीएसयू से संपर्क में है। आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई निविदा में सूचीबद्ध किया गया है।

- **परीक्षा के तीन सप्ताह पहले से होगी तैयारी–** दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा स्थलों की विस्तृत सूची और प्रत्येक स्थल के लिए उम्मीदवारों की संख्या यूपीएससी द्वारा टेक्नोलॉजी सर्विस को परीक्षा से दो से तीन सप्ताह पहले ऑन–साइट तैयार कर लिया जाएगा। यूपीएससी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान में उपयोग के लिए परीक्षा से सात दिन पहले उम्मीदवार का विवरण (नाम, रोल नंबर, फोटो आदि) भी प्रदान करेगा।
- **सर्विस प्रोवाइडर करेंगे उम्मीदवारों की पहचान–** दस्तावेज में कहा गया है, यूपीएससी द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/सत्यापन प्रक्रिया के समय, सर्विस प्रोवाइडर को परीक्षा के प्रारंभिक चरणों के दौरान प्राप्त किए गए उम्मीदवार डेटा से उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करनी होगी।

इंदौर को बजट में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मिली राशि

इंदौर के आसपास चल रहे रेल प्रोजेक्ट के लिए मिले लगभग 2500 करोड़ रूपए

इंदौर (एजेंसी)। केंद्र में पेश हुए बजट में इंदौर व आसपास की रेल परियोजनाओं को लेकर पर्याप्त पैसा मिला है। शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्रीय बजट मे इंदौर के आसपास चल रहे रेल परियोजनाओं के लिए भरपूर बजट प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट में इंदौर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट में सर्वाधिक 1080 करोड़ इंदौर-बुधनी के लिए मिले हैं। महू-आकोला गेज कन्वर्जन के लिए 910 करोड़, इंदौर-दाहोद को 600 करोड़ और धार-छोटा उदयपुर को 350 करोड़ दिए गए हैं। इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को मात्र एक हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में इंदौर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट के लिए अब तक के सर्वाधिक 2590 करोड़ दिए गए हैं। यही राशि चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में भी जारी की गई थी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, अब सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। जल्द इनकी टाइम लाइन बनाएंगे।

इंदौर-दाहोद-धार तक 2025 में ही ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य

इंदौर-दाहोद प्रोजेक्ट में रेलवे ने टनल थ्रू कर दी है। अब फिनिशिंग और पटरी बिछाने का काम होगा। टिही से आगे के हिस्से में काम चल रहा है। रेलवे का 2025 तक धार तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।

महू-खंडवा गेज कन्वर्जन: महू-खंडवा गेज कन्वर्जन में रेलवे ने सनावद से ओंकारेश्वर और महू-पातालपानी के बीच काम पूरा कर सीआरएस इंस्पेक्शन करा लिया है। ओंकारेश्वर के पास ब्रिज का काम चल रहा है। महू के आगे घाट सेक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

इंदौर-बुधनी- बुधनी की ओर से काम चल रहा है। अब इंदौर की ओर से भी काम शुरू होगा। हालांकि यहां जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस रेल लाइन से इंदौर-जबलपुर की दूरी 68 किमी कम होगी। नई लाइन 205 किमी लंबी है। फिलहाल जो ट्रेनें चलती है उससे यह दूरी 287 किमी की है।

इंदौर-मनमाड़ - प्रोजेक्ट में कुछ स्तर पर मंजूरी मिलना बाकी है। प्रोजेक्ट की राशि भी 22 हजार करोड़ से घटाकर कुछ कम की गई है।

* इंदौर-बुधनी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा 1080 करोड़।
* *इंदौर-धार व अमझेरा-दाहोद प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़।
* *छोटा उदयपुर-धार परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए।
* * इंदौर-उज्जैन दोहरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए।
* * इंदौर-खंडवा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 600 करोड़ रूपए।

मंत्री विजयवर्गीय बोले

इंदौर के लोग रबड़ी-रसगुल्ला खाना भूल गए...

अब जाने क्या-क्या पिज्जा, नूडल्स, मोमोस, फोमोज खाते हैं..

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के 6 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैंसर अभी बहुत बड़ी चुनौती है। ये न हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इंदौर के सरकारी अस्पतालों को हार्ट के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। हार्ट से जुड़ी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। पहले आदिवासियों में हार्ट, शुगर की बीमारी नहीं होती थी। पर अब वे इससे ग्रस्त होने लगे हैं क्योंकि उनका खानपान भी बदला है। मैं इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हैं कि आपको जो सुविधाएं चाहिए हैं हम उपलब्ध कराएंगे।

फूड हैबिट्स सुधारने की सलाह भी दी

विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं ऐसे शहर का प्रतिनिधि हूं जहां के लोगों ने रबड़ी-रसगुल्ला खाना छोड़कर पिज्जा, नूडल्स, मोमोस खाना शुरू कर दिया है। ये खाकर आप बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। खाने में मिलाए जाने वाले कई पदार्थ खतरनाक हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार अध्ययन कर ऐसे खाद्य पदार्थों को बैन करेगी। बच्चों को भी अपनी फूड हेबिट्स सुधारने की जरुरत है। ताकि वे बीमारियों से खुद को बचा सकें। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, यूएसए के एक्सपर्ट डॉ. प्रकाश सतवानी, डॉ. राहुल भार्गव (गुड़गांव), एम्स नई दिल्ली से डॉ. तुलिका सेठ भी मौजूद थे।

घातक खाद्य पदार्थों को बैन करेंगे

शहर में खानपान के नाम पर मिलने वाला आइटमों में कौन-कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं जो शरीर के लिए घातक है इसके लिए हमने खाद्य अधिकारी विभाग को बोला है कि वह जांच करके बताएं हम इस मामले को सरकार का अवगत करा कार्रवाई करेंगे

अब तक 103 ट्रांसप्लांट, 50 से ज्यादा वेटिंग में

यहां रक्त जनित बीमारी के 103 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। यह प्रदेश के किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि करी 50 मरीज अभी वेटिंग में हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 2018 में ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सेवा शुरू की गई थी । मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित और सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. सुमित शुक्ला ने बताया है कि 4 मार्च 2018 को पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था।

आज से इंदौर से खजुराहो के लिए सीधी फ्लाइट

पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन करने वाली फ्लाय ओला ने शुरू किया संचालन

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर से खजुराहो के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस मार्ग पर पहली बार सीधी उड़ान आज से शुरू होने जा रही है। उड़ान का संचालन पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत फ्लाय ओला कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस उड़ान की बुकिंग भी शुरू कर दी है और इंदौर से यह उड़ान पूरी तरह फुल भी हो चुकी है। वहीं खजुराहो से इंदौर आने वाली फ्लाइट की सीट खाली बताई जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली की जेट सर्व एविएशन प्रा.लि. (फ्लाय ओला) कंपनी के साथ मिलकर प्रदेश के 8 शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू की है। इसी कड़ी में कंपनी पहली बार इंदौर से खजुराहो के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। इसका संचालन भी 6 सीटर विमान के साथ ही किया जाएगा। कंपनी ने एक ओर का किराया डिस्काउंट के बाद 6300 रुपए रखा है। इसमें भोपाल के यात्री भी वाया इंदौर सफर कर सकेंगे। आज से संचालित होने वाली इस फ्लाइट के लिए इंदौर से सभी सीटें बुक बताई जा रही है, वहीं खजुराहो से इंदौर आने वाली फ्लाइट की सभी सीटें खाली हैं।

यह है फ्लाइट का शेड्यूल

- इंदौर से 3.30 बजे रवाना होकर शाह 5.30 बजे खजुराहो पहुंचेगी।

- खजुराहो से शाम 6 बजे रवाना होकर रात 8 बजे इंदौर पहुंचेगी।

डीएवीवी के बीएड के रिजल्ट पर बवाल

10 में से 6 हजार स्टूडेंट को आई एटीकेटी

इंदौर (एजेंसी)। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स ने सवाल खड़े किए हैं। 60 परसेंट स्टूडेंट्स का रिजल्ट बिगड़ गया है। उन्हें अलग-अलग विषय में एटीकेटी आई है। 40 परसेंट स्टूडेंट्स ही पास है। रिजल्ट बिगड़ने से स्टूडेंट्स ने मूल्यांकन पर सवाल खड़े किए हैं। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में इस संबंध में शिकायत की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार बीएड फर्स्ट सेमेस्ट की परीक्षा में 10 हजार स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। जिसमें से 4 हजार स्टूडेंट्स पास हए हैं। 6 हजार स्टूडेंट्स को एटीकेटी आई है। रिजल्ट बिगड़ने के बाद यूनिवर्सिटी की मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से कॉपी चेक नहीं करवाई जाती है। इस वजह से ये स्थिति बनी है।

नाम बदलकर होटल में रुके फारुख की पिटाई

महिला के साथ पकड़ाने पर बोला- दोस्त ब्रजेश की आईडी बताकर कमरा लिया था

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के विजयनगर की एक होटल बुधवार रात हंगामा हो गया। यहां महिला के साथ नाम बदलकर रुके युवक के साथ मारपीट की गई। बाद में उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। विजय नगर पुलिस के मुताबिक इलाके की निजी होटल में बुधवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां उन्होंने रीवा में रहने वाले फारुख खान को पकड़ा। होटल में उसने ब्रजेश नाम की आईडी दी। उसके साथ अन्य वर्ग की एक महिला थी। जब कार्यकर्ता अंदर घुसे तो उसने अपना नाम ब्रजेश ही बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना असली नाम और आईडी बता दी। फारुख ने कहा कि ब्रजेश उसके दोस्त का नाम है। वह उसी की आईडी लेकर आया था, होटल में भी ब्रजेश की ही आईडी लगाई। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फारुख को पकड़कर विजय नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है।

81 लाख फीस भरी, सीट छोड़ी तो 3 साल बैन

एमबीबीएस छात्रा का सवाल- एक गलती की दो सजा क्यों? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन लेने वाली छात्रा ने सीट छोड़ दी। उसने अपने डॉक्यूमेंट मांगे तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नियमों के मुताबिक पूरी फीस के 81 लाख रुपए जमा कराए लिए। इसके बाद छात्रा के 3 साल तक पीजी की काउंसलिंग में बैठने पर रोक भी लगा दी। छात्रा ने इस डबल कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने तीन बार जवाब देने के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को समय भी दिया, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से कड़े लहजे में कहा है कि इस संबंध में नियम जो भी हो, 14 अगस्त 2024 तक इसका जवाब पेश कर दें। वरना डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को खुद हाजिर होना पड़ेगा।

छात्रा ने कहा- हर्जाना दिया, फिर क्यों रोकी पढ़ाई?

छात्रा डॉ. रितिका माहेश्वरी ने 2023 में

अधिवक्ता आदित्य सांघी के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर रखी है। छात्रा की ओर से तर्क दिया गया - एमबीबीएस पासआउट स्टूडेंट किन्हीं कारणों से बीच में पीजी की पढ़ाई छोड़ दे तो उससे सीट खाली करने के बदले हर्जाना वसूला जाता है। मैंने भी 81 लाख रुपए हर्जाना चुकाया है। अब मुझे फिर से पीजी करना है, लेकिन एग्जाम क्लीयर करने के बावजूद मेरी काउंसलिंग पर तीन साल का बैन क्यों है? छात्रा का कहना है कि अगस्त में पीजी एग्जाम और उसके बाद काउंसलिंग है, यदि तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो 2024 में भी उसे मौका नहीं मिल पाएगा।

एक गलती, दो सजा को लेकर छात्रा का यह है तर्क

इंदौर के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी में छात्रा डॉ. रितिका माहेश्वरी ने एमबीबीएस के बाद पीजी एग्जाम दिया था। 2022 में पीजी कोर्स में एडमिशन मिल गया। बाद में व्यक्तिगत कारण बताकर डॉ. रितिका ने यह सीट खाली कर दी। सरकार का नियम है कि सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन के बाद सीट खाली करने पर खर्च स्टूडेंट ही उठाएगा। साथ ही अगले तीन साल तक वह इस एग्जाम की काउंसलिंग में वह बैन रहेगा।

श्री गंगा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निरस्त

इंदौर (एजेंसी)। देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी स्थित फर्म श्री गंगा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मंडी में 7 किसानों ने इस फर्म की शिकायत की थी। किसानों ने लिखित आवेदन दिया था कि हमारी उपज क्रय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। इस पर मंडी सचिव ने फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया। कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के सचिव नरेश कुमार परमार ने बताया शिकायत के अनुसार गंगा ट्रेडिंग कंपनी ने अरबअली के चार लाख 80 हजार, गोपाल के एक लाख 40 हजार, सागर यादव के 70 हजार, रामनारायण यादव के एक लाख 30 हजार, त्रिलोक यादव के एक लाख 79 हजार, सतीश के 2 लाख 49 हजार तथा संतोष के एक लाख 98 हजार रुपए नहीं दिए। इस शिकायत पर संबंधित फर्म से जवाब मांगा गया। जांच में पता चला कि फर्म ने किसानों का भुगतान निर्धारित पांच दिन की समय सीमा के बाद किया, जो मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (2) (ग) का उल्लंघन है। कृषि उपज मंडी समिति इंदौर द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 1 से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत उपरोक्त फर्म की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।

इंदौर पुलिस प्रशिक्षुओं को ग्राम भ्रमण कराया

पुलिस दल ने ग्रामीणों को दी जनहितैषी योजनाओं की जानकारी

इंदौर (एजेंसी)। सामुदायिक पुलिसिंग के दृष्टिगत संस्था प्रमुख उमनि/निदेशक के निर्देशानुसार संस्था में संचालित प्र.आर.(रे) से सहा. उप निरी. (रे) पी.पी. कोर्स क्र 11 के प्रशिक्षुओं को नवाचार के अंतर्गत ग्राम पालाखेडी थाना हातोद जिला इंदौर का भ्रमण कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जानने तथा पुलिस की जनहितैषी योजनाओं के बारे में उन्हें बताने तथा पुलिस की योजनाओं का लाभ लेने के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉयल-100 तथा सीसीटीवी जनता के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तथा इनकी कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही महिलाओं के अधिकार तथा पुलिस की उनके प्रति संवेदनशीलता को भी विस्तृत रूप से बताया गया। वर्षा के मौसम में होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, हैजा व जल जमाव से होने वाले नुकसान को रोकने और बचाव के बारे में बताया गया। पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है परंतु पुलिस भी आमजन से सहयोग की अपेक्षा करती है। संदिग्ध अपराधियों एवं अपराध की समय पर सूचना देकर जनता पुलिस को बहुत सहयोग कर सकती है तथा स्वयं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है।

मौसम में ठण्डक, बादल छाए

28 जुलाई से बनेगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इंदौर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में जुलाई में बारिश की बेरुखी अभी भी बनी हुई है। 15 जुलाई को हुई डेढ़ इंच हुई बारिश हुई थी। इसके बाद तेज बारिश नहीं हुई है और न ही अभी झड़ी के आसार हैं। दस दिनों से मौसम जरूर बारिश जैसा बन रहा है लेकिन स्ट्रॉन्स सिस्टम नहीं होने से जुलाई का कोटा आधे से भी कम है। गुरुवार सुबह से बादल छाए हुए थे और मौसम ठण्डा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 जुलाई के बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। इसके बाद इंदौर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी। आज भी रिमझिम के आसार है। इस सीजन की कुल बारिश सवा 10 इंच हुई है। जुलाई का कोटा 14 इंच का है और इस माह 6 इंच ही बारिश हुई है यानी आधे से कम। ऐसे में अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में अच्छी बारिश की उम्मीद है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक, मानसून ट्रफ ऊपर चली गई है। लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है। एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ गुजरात में है। यह मानसून ट्रफ के साथ मर्ज हो गया है। इन वजहों से प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि 28 जुलाई से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी हो सकती है। 29 और 30 जुलाई को उत्तरी हिस्से में तेज बारिश होने का अनुमान है। फिर इंदौर संभाग में गरज-चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।

गायत्री परिवार का अभियान

महिलाओं और बालिकाओं को दिया जा रहा है कंप्यूटर, सिलाई तथा कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण

इंदौर (एजेंसी)। गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी की धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा माताजी का जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में मनाया जाना है। इसी संदर्भ में वर्ष 2024 से लेकर जन्म शताब्दी तक की शेष अवधि मातृ शक्ति श्रद्धा संवर्धन वर्ष के रूप में मनाए जाने की तैयारी गायत्री परिवार ने की है। इसी श्रृंखला में इंदौर गायत्री परिवार ने अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया है। श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा संचालित गायत्री शक्तिपीठ केसरबाग रोड में मातृशक्ति श्रद्धा संवर्धन के अंतर्गत बालिकाओं तथा महिलाओं में स्वावलंबन, आत्म निर्भरता, आत्म स्वाभिमान, आत्म सुरक्षा की भावना को बलवती करने के उद्देश्य से, निःशुल्क कंप्यूटर, सिलाई तथा कराटे प्रशिक्षण गुरुपूर्णिमा से प्रारंभ किया गया है। इसी के साथ गायत्री परिवार की बहनों के लिए संगीत का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया गया। वर्तमान में लगभग 50- 50 महिलाएं तथा बालिकाएं निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

आत्म सुरक्षा के अंतर्गत कराटे का प्रशिक्षण

इसी प्रकार आत्म सुरक्षा की भावना को बलवती करने के लिए शक्तिपीठ पर बालिकाओं को निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है । प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व सभी बालिकाएं और महिलाएं गायत्री मंत्रलेखन करती हैं। इस प्रकार शक्तिपीठ पर उनमें स्वावलंबन, आत्म विश्वास, आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, आत्म सुरक्षा के साथ आध्यात्मिकता की भावना भी विकसित हो रही है।

सराफा से 35 ग्राम सोना ले गई महिला चोर

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के सराफा बाजार से दो महिला चोरों ने 35 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिये। वह अपने साथ दो नाबालिग बच्चों को लेकर पहुंची थी। चोरी के बाद वह करीब दो से ढाई घंटे तक बाजार में घूमती रही। सोना-चांदी व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। सराफा पुलिस के मुताबिक बुधवार को मोहन लाल पुत्र छोटेलाल सोनी निवासी गफ्फूर खां की बजरिया थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोपहर में दो महिलाएं बच्चों को लेकर दुकान पर आई थी। उन्होंने सोने के टॉप्स दिखाने को कहा। इस दौरान दुकान पर रखे दूसरे जेवर पर हाथ साफ कर दिया। शाम को जब स्टॉक चेक किया तो करीब 35 ग्राम सोने के टॉप्स गायब मिले। मोहनलाल के मुताबिक उनकी दुकान पर कैमरे नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने शंका के आधार पर मार्केट के सीसीटीवी चेक किये तो संदिग्ध महिलाओं की पहचान की है। जिसमें महिलाएं दूसरी अन्य दुकानों पर भी जेवर देखने पहुंची थी। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

संपादकीय

तेवर ठंडे पर चिंगारी बाकी

मप्र के आदिवासी मंत्री नागरसिंह चौहान द्वारा उनसे वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग छीन कर नए और कांग्रेस से भाजपा में शामिल मंत्री रामनिवास रावत को देने से बगावत की जो आग भड़काई गई थी, वह अब आलाकमान के सख्त तेवर और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की 'समझाइश' के बाद ठंडी जरूर पड़ गई है, लेकिन असंतोष की चिंगारी बुझ गई है, ऐसा मानना गलत होगा। राज्य के आदिम जाति कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान ने अपने दो अहम विभाग छीने जाने से नाराज होकर यह बम फोड़ा था कि वो अपनी सांसद पत्नी अनीता चौहान से भी लोकसभा से इस्तीफा दिलवा देंगे। नागरसिंह का यह भी कहना था कि विभाग कम करने का फैसला उन्हें विश्वास में लिए बगैर किया गया। आशय यह था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनका कद कम करना चाहते हैं। मंत्री की नाराजी से ज्यादा उनकी पत्नी के इस्तीफे की धमकी की गूंज दिल्ली तक पहुंची और पार्टी आलाकमान ने सख्त रवैया अपनाकर कड़ा संदेश दिया कि किसी को मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा। किसे क्या देना है और नहीं देना है, यह पार्टी का फैसला है। उसे सबको मानना ही पड़ेगा। चाहे फिर वह कोई भी हो। दरअसल नाराज नागर सिंह की इस्तीफे की धमकी के बाद पार्टी हाई कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया था। लेकिन वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने मुलाकात का समय नहीं दिया। लेकिन दिल्ली में नागरसिंह ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। तीनों नेताओं से मीटिंग करने के बाद नागर सिंह वापस भोपाल आए और सीएम से मुलाकात की। सवाल यह है कि नागरसिंह ने इतनी हिम्मत किस की शह पर दिखाई। चर्चा यह भी है कि नागरसिंह के असंतोष को भाजपा का ही एक खेमा हवा दे रहा है। नागर विवाद को आदिवासी बनाम ओबीसी रंग देने की भी कोशिश की गई। नागरसिंह के भी पहले रावत के भाजपा में प्रवेश और उन्हें मंत्री बनाने को लेकर नाराजगी का बम पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और बाद में अजय विश्नोई ने फोड़ा था और विश्नोई तो अभी भी खफा हैं। हालांकि यह दोनों नेता भी शिवराज विरोधी खेमे के ही माने जाते हैं लेकिन नई सरकार में हाशिए पर हैं। दोनों मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन नागरसिंह का मामला थोड़ा अलग है। वो आदिवासी समुदाय से हैं और भाजपा आदिवासियों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में नागरसिंह प्रकरण से गलत संदेश जा रहा है। नागरसिंह उन्हें विश्वास में न लेने की जो बात कह रहे हैं, अगर वो सही है तो भाजपा को अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार करना चाहिए। विभाग कम करने का काम नागरसिंह को बताकर भी किया जा सकता था। सांसद पत्नी से इस्तीफा दिलवाने के दांव का सुझाव नागरसिंह को किसने दिया, कहना मुश्किल है। पर इसने आलाकमान को नाराज कर दिया, यह बहुत साफ है। क्योंकि केन्द्र में भाजपा अल्पमत की गठबंधन सरकार चला रही है। एक सांसद भी कम होना खतरे की घंटी है। नागरसिंह फिलहाल भले चुप हो गए हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पार्टी में असंतोष के स्वर भी खामोश हो गए हैं। लगातार चुनाव जीतने के बाद भी मप्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं में नाराजगी कायम है। संदेश यह जा रहा है कि अपनों से छीनकर आयातित नेताओं को बांटा जा रहा है। वैसे भी रावत को भाजपा में लाने से क्या लाभ है, समझना मुश्किल है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। संप्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

विश्व की भलाई में भारतीय विरासत का वैशिष्ट्य

भारत के यशोगान में संपूर्ण विश्व कहता है कि इसकी स्थापनाएं ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। इसके भलाई के गीत प्रशंसनीय हैं। इसका वैशिष्ट्य शांति, ज्ञान व मैत्री से प्रतिष्ठित है। यह देश अब पूरी पृथ्वी पर अपने जिस स्वभाव से जी रहा है, इसका अतीत कहीं इससे भी विपुल था। भारतीय विरासत की इसलिए विश्व स्तर पर अपनी अहमियत है। जब भारत ने जी-20 शिखर सम्मलेन की मेजबानी कर रहा था तो जिस थीम के साथ उसने मेजबानी की उसमें भी यह स्पष्ट रूप से उभरकर आई कि भारत अपने अतीत की शब्दशक्ति के अतिरिक्त इच्छाशक्ति से भी धनी है। उसने वैश्विक स्तर पर नारा दिया एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। यह एक नारा नहीं है अपितु सच में यह उसकी वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा है। यह उसके हृदय का विस्तार है। संपूर्ण ब्रह्माण्ड के कल्याण की भावना रखने वाला भारत अपनी विरासत में अपने अभीष्ट को देखता है। उसका अभीष्ट है सत्यनिष्ठ जन-जीवन, सुन्दर पृथ्वी और सृष्टि का उत्सर्ग। यह अभीष्ट विश्व की उन सभी बुराइयों का प्रतिरोध करने में सक्षम है।

भारत की संस्कृति के प्रदर्शन हेतु विश्व धरोहरों के ही ओर हम जाते हैं। एक अच्छी बात यह हुई है कि विदेशों से लौटी कलाकृतियों को लेकर भारत उत्साहित हुआ और ये कलाकृतियाँ सैकड़ों हैं। भारत की 350 से अधिक धरोहर वस्तुओं को वापस लाया गया है। यह भारत की अपनी सांस्कृतिक वस्तुओं को सहेजने वाले दुसरे देश में कौन लोग हैं? उन्होंने निश्चय ही भारत पर बहुत उपकार किया है। हमारी धरोहरों को सुरक्षित रखा है और अब वे भारत को सौंपकर अपने नागरिक दायित्व का केवल परिचय नहीं दे रहे हैं अपितु वह विश्व विरासत के संरक्षक बन गए हैं जो कि अभिनंदनीय है। खास बात यह है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में, 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक हो रही है जिसका मेजबान भारत है।। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व धरोहर सहेजने के प्रयासों के लिए 10 लाख डॉलर धनराशि देने का ऐलान किया है। यह भारतीय विरासतों के साथ वैश्विक विरासतों को संरक्षित करने हेतु जो भारतीय निवेश है, उल्लेखनीय उपलब्धियों का करक बनने वाला है।

भविष्य के समझौते हेतु संयुक्त राष्ट्र में कुछ महीने बाद जब सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इकठ्ठा हो रहे हैं, उस समय भारत का विश्व की विरासत के लिए किया जाने वाला निवेश अतिमहत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले ने कहा भी कि अपने समृद्ध अतीत के आधार पर भारत, विरासत संरक्षण को अन्तरराष्ट्रीय एजेंडे में सबसे आगे लेकर आया है। जी-20 की अध्यक्षता व मेजबानी के वक्त पहली बार 2030 के बाद के सतत विकास एजेंडे में संस्कृति को केन्द्र में रखने का आहवान हुआ और अब यह जब निवेश हुआ है तो इसे विशेषज्ञ यह मान

रहे हैं कि भारत ने निवेश के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया था, और उसने निभाया भी है।, भारत ने संस्कृति को एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान्यता दिलाने में मदद की है, यह भारत की उपलब्धि है। भारत की इसके बाद यह भी उपलब्धि बनने जा रही है कि सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने वाले भविष्य के समझौते में जगह मिलने वाली है।

अब तो धरोहरों को सहेजने व विरासत को बनाये रखने की चुनौती एआर व वीआर प्रणाली आने से कम हुई है। विश्व के विभिन्न देशों में यह कोशिश हो रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के माध्यम से विरासत को बचाया जाए। इसे कुछ राष्ट्र के कॉर्बन के दुष्प्रभाव पर काम करने वाले वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इसके माध्यम से हम कम निवेश व कम मेहनत से विरासत बचा सकेंगे। भारत इस दिशा में काम कर रहा है की एआई के माध्यम से कैसे विरासत को दीर्घजीवी व सतत बनाए रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों में निःसंदेह हमारे देश के नेतृत्व का बड़ा हाथ है। अतुल्य भारत तो भारत की एक योजना है जिसमें वह विश्व को जोड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व प्राच्य सांस्कृतिक, साभ्यातिक विविधताओं में लिपटे विश्व को आश्चर्य की निगाह से इसलिए आज का मानव समाज देखता है क्योंकि इसके अर्वाचीन अवर्णनीय छटा में इतने रहस्य हैं और इतनी जिज्ञासाओं के लिए स्थान है कि वे हमें अपनी ओर लुभाते हैं। वे हमें आकर्षित करते हैं कि तुमरे पूर्वज और उनके द्वारा सुरक्षित तुम्हारी विरासत का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। विश्व की भौगोलिक, विविधता, भाषाई विविधता, जीवनशैली, प्रकृति व जलवायु ने अलग-अलग हिस्से में मनुष्य को उदित होने दिया और मनुष्यों ने विरासतों को सहेजा भी और रौंदा भी। इस व्यापक संघर्ष से बची हुई विरासतें हमारे अतीत से हमें मिलाती हैं। हमें हमारे अतीत पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती हैं। वे महान सभ्यताएं निश्चय ही हमें आगे बढ़ने और कुछ नया सृजित करते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। भारत का विरासतों के लिए किया जाने वाला संघर्ष इसीलिए एक महान कार्य है।

अभी मई महीने में भारत की 'रामचरित मानस', 'पंचतंत्र' व 'सहृदयलोक-लोकन' को जब विश्व विरासत में शामिल किया गया था तो उस पल को स्मरण करें। पूरे भारत में जश्न मनाया गया। रामचरित मानस व पंचतंत्र से सभी परिचित हैं। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी ई।पू। की कृति 'सहृदयलोक-लोकन', संस्कृत भाषा में है, उसके बारे में सभी परिचित नहीं हैं। इसमें काव्य, नाट्यशास्त्र और नाट्य अंतर्दृष्टि से सम्बन्धित पाठ और चर्चाएँ शामिल हैं। निःसंदेह ये तीनों साहित्यिक उपलब्धि भारत के लिए उसके गर्व की विषय हैं जिनसे हमारा समाज प्रेरणा लिया और अपनी व आने वाली पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त किया। भारत की विरासतों की तरह दुनिया की महान विरासतों का इतिहास पृथ्वी के सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय हैं। भारत का विरासत संरक्षण के लिए निवेश दुनिया की भलाई के रूप में ही देखा जा रहा है।

इस निवेश के बाद दुनिया के समक्ष भारत का स्पष्ट यह संदेश है कि वे भी इस दिशा में निवेश करें। देशों को इससे लग सकता है कि इस निवेश से बड़ी चुनौती भारत ने खड़ी कर दी है। वे इसके लिए धन का निवेश करें या युद्ध से निपटें। युद्धरत देशों के मुह पर भारत का यह जोरदार तमाचा है। लड़ने की जगह सृजन, संरक्षण व सुरक्षित भविष्य की पुकार ज्यादा ज़रूरी है। हम सब अपने पूर्वजों की विरासतों को, प्रकृति की विरासत को बचाने से जो बच रहे हैं वह हमारे लुप्त होते साँझा नुकसान हैं। इसकी भरपाई न किसी ने की और न कोई कर पायेगा। भारत में ही ऐसी अनेक भाषाएँ लुप्त हो गयीं। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियाँ भी लुप्त हुई होंगी, जिसको हम नजरंदाज़ कर रहे थे। उसे वापस आज कोई नहीं ला सकता। अब तो एक सामूहिक पहल के साथ निवेश की इस दिशा में जरूरत है की हम विश्व विरासत के वैशिष्ट्य को समझें और उसे बचाने के भरपूर कोशिश करें। आज भले ही निरर्थक यह पहल लगती हो लेकिन हज़ार-दो हज़ार वर्ष बाद जो हमारी पीढ़ी होगी, उनका हम बड़े पैमाने पर जो नुकसान कर चुके होंगे, वह हमारे दायित्व को ही प्रश्नांकित करेंगी। भारत इस वर्ष जो विरासत संरक्षण के हिमायतियों के साथ परिचर्चा कर रहा है, इसका यदि परिणाम निकले तो पूरे विश्व का इसमें लाभ होने वाला है।

कलरफुल इंडिया

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

यदि बजट कांग्रेस घोषणापत्र की 'कॉपी' है तो आलोचना क्यों?

राहुल गांधी का यह कथन कि बजट "कांग्रेस के घोषणा पत्र की "कापी पेस्ट" है", समझ से परे है। यह बजट की आलोचना है अथवा प्रशंसा? अगर एनडीए सरकार का बजट कांग्रेस के घोषणापत्र का 'कॉपी पेस्ट' है, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को रूबरू भाजपा ने अपने बजट में अपना लिया है। तब तो इस बात के लिए राहुल गांधी को भाजपा की प्रशंसा करनी चाहिए थी। यदि यह आलोचना है तो उसका मतलब तो यह निकलता है कि भाजपा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो गलत है को अपना लिया है। इसलिए राहुल गांधी ने आलोचना की है।

हमारे देश में पक्ष व विपक्ष के बीच खाई इतनी गहरी हो गई है कि परस्पर एक दूसरे की आलोचना करते समय वे प्रायः तथ्यों से परे हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बजट पर प्रतिक्रिया व उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का कथन इसी श्रेणी में आता है। राहुल गांधी ने अपनी बजट प्रक्रिया में तीन मुख्य बातें कहीं हैं। पहला यह ''कुर्सी बचाओ बजट है'', जो बिल्कुल सही है। लेकिन कृपया वे यह बतलाने का कष्ट करें कि 77 साल की स्वाधीनता की अवधि में किस वर्ष का, किस सरकार का बजट 'कुर्सी बचाओ' के बजाय ''कुर्सी गिराओ'' या ''कुर्सी खोने'' वाला बजट रहा है? दूसरा कथन सहयोगियों को खुश करने की कोशिश में सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर 'खोखले वादे' किए हैं। यह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। क्योंकि सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज 15 हजार करोड़ रू. का व बिहार के लिए 26 हजार करोड़ रु. का प्रावधान किया है, जिससे दोनों राज्य सरकारें संतुष्ट हैं। अतः यह खोखला वादा कैसे हो सकता है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कथन इस बजट को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट की नकल करार दिया है।

राहुल गांधी का यह कथन कि बजट''कांग्रेस के घोषणा पत्र की ''कापी पेस्ट'' है'', समझ से परे है। यह बजट की आलोचना है अथवा प्रशंसा? अगर एनडीए सरकार का बजट कांग्रेस के घोषणापत्र का 'कॉपी पेस्ट' है, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को रूबरू भाजपा ने अपने बजट में अपना लिया है। तब तो इस बात के लिए राहुल गांधी को भाजपा की प्रशंसा करनी चाहिए थी। यदि यह आलोचना है तो उसका मतलब तो यह निकलता है कि भाजपा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो गलत है को अपना लिया है। इसलिए राहुल गांधी ने आलोचना की है।

सिक्के के दो पहलू

हर सिक्के के दो पहलू के समान बजट के भी दो पहलू हैं। कुछ विशेषताएं तो कुछ कमियां! बजट का दोनों आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से आकलन किया जाना आवश्यक है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के समस्त लोगों की हर खाहिशें की पूर्ति कोई एक बजट नहीं कर सकता है। हाँ उस दिशा में जरूर आगे बढा जा सकता है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से बजट की आकलन करे तो, इसका सबसे बडा बैरोमीटर (पेरामीटर) बजट के तुंरत बाद आई शेयर मार्केट की प्रतिक्रिया है, जो बजट पेश करने के पूर्व 220 अंक से भी ज्यादा बढ़ा हुआ खुलकर बजट प्रस्तुत होने पर 1200 अंक से ज्यादा सूचकांक गिर गया। मतलब आर्थिक दृष्टि से बजट ठीक नहीं रहा। शायद इसका एक कारण दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.50 व अल्पकालीन पूंजीगत लाभ (एसटीटी) पर 15 से 20 प्रतिशत कर देना भी हो सकता है। एलटीटी की दर में भी बढ़ोत्री की गई है।

बैसाखी देने वाले साथियों को साधा गया

राजनीतिक दृष्टि से एनडीए के दोनों साथियों जेडीयू एवं तेलुगूदेशम को साधने में सरकार सफल रही है, जिनकी बैसाखी पर सरकार खडी है। इस आधार पर कांग्रेस की आलोचना नितांत गलत है। क्योंकि उसने भी यूपीए के समय अपने साथियों की इच्छाओं की पूर्ति की थी।

बजट की विशेषताएं

निश्चित रूप से हर बार के बजट के समान इस बार के बाजार की भी अपनी कुछ विशेषताएं व अच्छाइयां है, जिनका स्वागत किया जाना चाहिये। मुद्रास्फीति की दर 3.1 प्रतिशत तक सीमित रखी गई। रोजगार के मुद्दे पर पिछला चुनाव लड़ा गया था, जिस पर ज्यादा ध्यान केन्द्रीत कर शिक्षा व रोजगार पर 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढाकर 20 लाख करना, नये युवा रोजगार के लिए 7.5 लाख की नई स्कीम तथा 3 प्रतिशत की दर से छात्रों को ऋण देना। ये सब रोजगार को संबोधित करने वाले प्रावधान हैं। 80 करोड़ लोगों को दी जाने वाली मुफत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है।

आयकर संबंधी छूट

आयकर छूट की इस दृष्टि से यह बजट ' डिफॉल्ट का सहयोगी व डिपॉजिट का असहयोगी है,'' तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आयकर कानून की धारा 80 सी (चेप्टर 6) के अंतर्गत निवेश की सीमा रू. 1.5 लाख से नहीं बढ़ाई गई जो सालो पूर्व से बनी हुई है। क्या सरकार बचत को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है? टीडीएस की त्रुटि के लिए धारा 276 बी के अभियोजन के प्रावधान को समाप्त किया गया। दूसरा, कराधान की दो टैक्स स्कीम है। पहली स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब सरकार खुद यह कहती है कि नई कर व्यवस्था को दो तिहाइयों से ज्यादा लोगों ने अपनाया है, तब सरकार पुराने को समाप्त क्यों नहीं कर देती है। विभिन्न आय वर्गों के स्लैब में जो छूट आयकर की दरों में दी गई, वह स्वागत योग्य है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जो अपवंचित आय के लिए लिमिटेशन 10 साल की थी, को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया व उसकी न्यूनतम सीमा भी 50 लाख रू. कर दी है। 'विवाद से विश्वास' स्कीम योजना 2024 फिर से लाई जा रही है। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स एक्ट कर दिया है। संक्षिप्त में जिस प्रकार भोजन के स्वाद में नमक-मिर्च, खट्टा-मीठा होने से जायका अच्छा होता है वैसे ही इस बजट का टेस्ट भी है। अतः इसका संपूर्णतः इस बजट का स्वागत किया जाना चाहिए।

पानी के लिए जनांदोलन जरूरी

जलसंकट

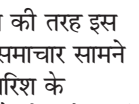

मोहन वर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

इन दिनों लगातार देश भर से और विदेशों से भी यहां वहां दिनों दिन कम होते जल स्तर की चिंता के साथ भविष्य में पानी की कमी को लेकर मंथन जारी है। हर बरसात की तरह इस बार भी कहीं से बाढ़ के समाचार सामने आ रहे है तो कहीं कम बारिश के समाचार भी सुनाई दे रहे है। देश के उपरी हिस्सों में अतिवृष्टि के, ग्लेशियर पिघलने के और पहाड़ों के धंसने की खबरें नई नहीं है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों से अलग इधर मध्यप्रदेश, राजस्थान,महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश के कम या ज्यादा होने के बावजूद जमीन के जल स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है।

जमीन के जलस्तर में बढ़ोतरी के लिए देवास शहर में इस बार दो माह तक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अमृत संचय अभियान चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और सोक पिट के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना था। भूजलविद डॉ. सुनील चतुर्वेदी का साथ और जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता के सहयोग,मार्गदर्शन से इस बार देवास शहर ने दो सौ करोड़ लीटर पानी बचाने के अपने उद्देश्य में सफलता पाकर एक मिसाल कायम की है।

सफलता की इस कहानी की बात करें तो जिले में लगातार गिरते जल स्तर और भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए इस अभियान को हाथ में लिया गया था।जिलाधीश गुप्ता ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट कलेक्टर प्रियंका मिमरोट को नोडल अधिकारी बनाया और फिर तो देवास के उद्योगों से लेकर सरकारी भवन तक और मैरिज गार्डन से लेकर,वेयर हाउसेस तक,सभी प्रायवेट और सरकारी स्कूलों से लेकर निजी भवनों तक लोग आते गए कारवां बढ़ता गया ।

जब इस अभियान में टीम लीडर भूजलविद डॉ. सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि एक बारिश में एक हजार वर्ग फिट की छत से तकरीबन सवा लाख लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है जिसे यदि वाटर हार्वेस्टिंग या सोक पिट के माध्यम से जमीन में उतारा जाए तो जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती है। बस टीम लग पड़ी और परिणाम सामने आने लगे।

शहर के एक कालोनाईजर की बात करें तो वहां अलग अलग संरचनाओं के माध्यम से उनकी 38 हजार वर्गफुट जमीन पर 28 रिचार्ज पिट बनाई गई और मात्र दो तीन बारिश के बाद ही जलस्तर में 10 फीट की बढ़ौतरी के परिणाम सामने आ गए। किसी उद्योग ने इस बारिश में दो करोड़ पानी बचाया तो किसी ने बीस करोड़।

काम मुश्किल था लेकिन जब कोई अभियान जनआंदोलन बन जाय तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है । यह जनआंदोलन की ही ताक़त थी कि पानी बचाने में देवास ने फिर एक बार इतिहास रच दिया । पानी बचाने के लिये जहां जैसी ज़रूरत थी वहाँ वैसे तरीक़े अपनाये गये । बारिश का पानी बचाने के लिये सभी संरचनायें बिना किसी सरकारी मदद के जन सहयोग से तैयार की गयी और अभियान में जुटी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की टीम दो माह तक यहां वहां भागती दौड़ती रही जिसका परिणाम यह हुआ कि शहर ने इस बार वाटर हार्वेस्टिंग और सोक पिट के माध्यम से तयशुदा 200 करोड़ लीटर पानी संचित करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जो एक मिसाल है। सलाम देवास!

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बजट कथा: 'धन्नू काका' की भैंस की तरह बजट

गांव के बाहरी इलाके में लगे पशु मेले की हवा में ठंड और तंबू की गंध ने सबको अपने रंग में रंग दिया था। इस मेले का खास आकर्षण था–भैंस और गाय। लेकिन इस बार मेला खास था, क्योंकि यहां 'बजट' का लाइव शो चल रहा था!

अब सुनिए, कैसे यह शो गांव के दांवपेंच में बदल गया। गांव के प्रधान जी की भैंस, 'मुंबई चाची', बिकने के लिए आई थी। चूंकि इस भैंस का नाम अनोखा था, इसे बेचने के लिए दो दलालों की जरूरत थी–'सेठ रामु' और 'सेठ बलराम'।

सेठ रामु ने ग्राहक के लिए भाव बढ़ाने का ठेका लिया था, और सेठ बलराम ने मोलभाव की जिम्मेदारी संभाली थी। भैंस के मालिक, 'धन्नू काका', ने अपनी भैंस की कीमत 15 हजार रुपये तय की।

सेठ बलराम ने हंसते हुए कहा, '15 हजार की भैंस? हज़ार रुपये में भी मिल जाए, तो भी अच्छा रहेगा!'

सेठ रामु ने मौका पाया और खुद को मोलभाव का सीनियर एक्सपर्ट घोषित कर दिया। काका ने कहा, 'भाई, इतनी कीमत पर बेचूंगा तो घर में चाय भी नहीं बनेगी।'

अब सेठ बलराम ने दिमाग लगाया और बोला, 'काका, 15 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन हम ग्राहक को थोड़ा मनाएंगे।'

फिर क्या था, दलालों ने मिलकर तगड़ी मोलभाव शुरू की। सेठ बलराम ने भैंस के गले में चम्मच लटका दिया, जैसे भैंस के गले का हार उसकी कीमत घटा रहा हो।

धन्नू काका ने सोचा, 'ये तो अपने ही गांव के हैं, और वो भी दो-दो। अब भैंस बिकी तो बिकी, नहीं तो सब लूट ही लूट है।'

आखिरकार, दलालों ने मिलकर भैंस की कीमत 7 हजार रुपये कर दी। भैंस का मालिक, जो इस पूरे खेल को बस देख रहा था, चिढ़ गया और बोला, 'ये क्या मजाक है! मेरी भैंस की कीमत तुम दोनों मिलकर तय कर रहे हो!'

सेठ रामु ने बड़ी संजीदगी से कहा, 'देखिए काका, हम आपकी भैंस के लिए जी-जान लगा रहे हैं। कीमत तो हमारी मेहनत के अनुसार ही होगी।'

सेठ बलराम ने भी समर्थन किया, 'हां, हां, काका। आपको क्या, हम इस भैंस को 7 हजार में बेच रहे हैं।'

धन्नू काका ने गुस्से में कहा, 'मेरी भैंस, मेरी कीमत, और तुम दोनों ने मिलकर इसे आधी कीमत पर बेच दिया! क्या मैं तुम्हें बिकाऊ विधायक दिखता हूँ?'

दोनों दलाल हंस पड़े और बोले, 'अरे काका, यही तो लोकतंत्र है। सबके हिसाब से सब कुछ चलता है। हमने ही बजट बनाया है!'

काका ने सोचा, 'मतलब, अब मेरी भैंस ही नहीं, मेरी किस्मत भी इनके हाथ में है। अब हमें कोई समझाए कि यह 'भैंस बजट' कितना महंगा है?'

फिर काका ने भैंस को सौंपा और खुद कोने में बैठकर सोचने लगे, 'लोकतंत्र और बजट, दोनों का खेल बड़ा मजेदार है–बजट में मैं हूं और मेरी भैंस, और सब लोग अपने हिसाब से कीमत तय कर रहे हैं।'

इस प्रकार, गांव का यह पशु मेला 'बजट मेला' बन गया और सब लोग हंसते-खेलते चले गए।

तो अगली बार जब आप बजट की बात सुनें, याद रखें, कहीं यह बजट भी किसी 'धन्नू काका' की भैंस की तरह न बन जाए।

26 जुलाई विशेष

कारगिल फतह : भारत माता के माथे पर शौर्य का टीका

प्रो. मनोज कुमार

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं शोध पत्रिका समागम के संपादक हैं)

भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज़ों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊँचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था।

युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है लेकिन जब बात देश की अस्मिता, सुरक्षा और सम्प्रभुता पर आए जाए तो एकमात्र विकल्प युद्ध शेष रह जाता है। 25 वर्ष पहले भारत के चिर-परिचित दुश्मन पाकिस्तान ने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। दो माह की लम्बी लड़ाई के बाद भारत युद्ध फतह करने में कामयाब रहा। भारतीय नौजवानों ने अपने खून से भारत माता के माथे पर शौर्य का टीका लगाकर उसके मान में श्रीवृद्धि की। इस कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब दो महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाँबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18 हजार फीट की ऊँचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 750 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़ के भाग गए।

भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज़ों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाली जगहों पर हमला किया और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊँचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था।

पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने रुशष्ट करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान को इस लड़ाई में धूल चटाई, बल्कि शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना गई। इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही हो गई थी जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाडियों पर 5 हजार से भी ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी।

8 मई 1999 को पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इंफैंट्री के कैप्टन इफ्तेखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में इन चरवाहों को बंदी बनाने को लेकर चर्चा की, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐसा करने की सूरत में चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे, तो उन्होंने उन्हें वहां से जाने दिया। कुछ देरा बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे, और पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खुल गई।

पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ लाइन को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर हो कर सियाचिन छोड़ना पड़े। दरअसल, मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वह पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए।

कारगिल की लड़ाई शुरू में भारत के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन बोफोर्स और एयर फोर्स की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बोफोर्स तोपों के हमले तो इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और भारतीय सैनिकों की दिलेरी के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी। वहीं, कारगिल में वायु सेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज सुनाई पड़ती, वे बुरी तरह घबरा जाता थे और इधर उधर भागने लगते थे। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरूआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी जब उसने कारगिल की ऊँची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहाँ भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहाँ बम गिराए गए। इसके अलावा मिग-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर आर-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब दो लाख पचास हजार गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में एक राउंड फायर किया गया। बतायाक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी।

भारत ने बहुत कुछ खोया, पर पाकिस्तान बर्बाद हो गया कारगिल की लड़ाई में भारत ने जहां बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गए। वहीं, भारत में जंग ने देशप्रेम को उफान पर ला दिया और अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिली।

इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान को इस लड़ाई में धूल चटाई, बल्कि शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना गई। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को ही हो गई थी जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाडियों पर 5 हजार से भी ज्यादा सैनिकों के सा घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी।

भारत ने एलओसी क्यों नहीं पार की?

भारत के पास कारगिल युद्ध में जीत के बाद पीओके पर कब्जा करने का मौका था और भारत ऐसा कर भी सकता था लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कई कारण है। इनमें से सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत 1971 के शिमला समझौते के तहत एलओसी की स्थिति को बनाये रखना चाहता था। अमेरिका और चीन सहित दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की इस घुसपैठ को आक्रामक रूप में देखा क्योंकि पाकिस्तान ने एलओसी पार कर लिया था। भारत ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि यह एक नए युद्ध की शुरुआत भी हो सकती थी। यदि भारत ऐसा करता तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी सेना को पंजाब, जैसलमेर जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में मोर्चा खोलने का बहाना मिल जाता। पाकिस्तान ये भी नहीं मान रहा था कि कारगिल में उसकी ही सेना लड़ रही है। इसलिए अगर भारत सीमित ऑपरेशन रखेगा तो इससे युद्ध नहीं होगा इसलिए भारत ने ऐसा नहीं किया। कारगिल युद्ध इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान की पराजय और भारत की विजय के रूप में दर्ज है। भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले इसके पहले भी अन्य देशों ने पराजय का मुँह देखा है और पाकिस्तान को 25 वर्ष पहले एक बार फिर पराजय का मुँह ताकना पड़ा। भारत की नीति शांति की रही है लेकिन बात जब देश पर आती है तो वह आने वाले समय में ऐसे कई कारगिल विजय हासिल करने के लिए तैयार है। भारत माता के माथे पर शौर्य और विजय का टीका लगाकर हमारे वीर जवान संदेश देते हैं हमसे जो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। विजयी सैनिकों का भारत इश्तकाबाल करता है और जिन्हें खोया उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता है।

कारगिल विजय दिवस

मिसाल कायम करते झुंझुनू के जवान

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है।)

राजस्थान में झुंझुनू जिले के नवयुवकों में सेना में भर्ती होने की बहुत पुरानी परम्परा रही हैं। यहां के गांवों में घर-घर में सैनिक होता हैं। सेना के प्रति यहां के लगाव के कारण अंग्रेजों ने यहां एक सैनिक छावनी की स्थापना कर 'शेखावाटी ब्रिगेड 'का गठन किया था। देश रक्षा के लिये सेना में शहादत देना राजस्थान की परम्परा रही है। झुंझुनू जिले के वीर जवानों को उनके शौर्यपूर्ण कारनामों के लिये समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न अलंकरणों से नवाजा जाता रहा हैं। अब तक इस जिले के कुल 130 से अधिक सैनिकों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जो पूरे देश में किसी एक जिले के सर्वाधिक हैं। भारतीय सेना में योगदान के लिये झुंझुनू जिले का देश में अव्वल नम्बर हैं। वर्तमान में इस जिले के 55 हजार जवान सेना में कार्यरत हैं। वहीं जिले में करीबन 60 हजार भूतपूर्व सैनिक व अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। आजादी के बाद भारतीय सेना की और से राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हुये यहां के 486 जवान शहीद हो चुके हैं। जो पूरे देश में किसी एक जिले से सर्वाधिक है। कारगिल युद्ध के दौरान पूरे देश में 527 जवान शहीद हुये थे जिनमें यहां के 19 सैनिक शहीद हुये थे जो पूरे देश में किसी एक जिले से शहादत देने वालों में सर्वाधिक जवान थे। झुंझुनू जिले से अब तक 486 से अधिक सैनिक जवान सीमा पर शहीद हो चुके हैं।

राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले के अमर सपूतों की इस वीर भूमि के रणबांकुरों ने जहां स्वतंत्रता पूर्व के आन्दोलनो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेना द्वारा लड़ी गयी लड़ाइयों में भी इस धरती की माटी में जन्मे वीरों ने समय-समय पर अपना पराक्रम दिखाया हैं। वीरों की इस धरती ने सदियों से जन्म लेते रहे सपूतों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रवाहित किया हैं। वास्तव में यहां की धरती को यह वरदान सा प्राप्त होना प्रतित होता हैं कि इस पर राष्ट्रभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करने वाले लाडेसर ही जन्म लेते हैं। चाहे 1948 का पाकिस्तानी कबायली हमला हो या 1962 में चीन से युद्ध हो या 1965 व 1971 का भारत-पाक युद्ध। यहां के वीरों ने मातृभमि की रक्षा हेतू सदैव अपना जीवन बलिदान किया हैं। सेना के तीनों अंगो की आन की रक्षा के लिये यहां के नौजवान सैनिकों के उत्सर्ग को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता हैं।

राजस्थान में झुंझुनू जिले के नवयुवकों में सेना में भर्ती होने की बहुत पुरानी परम्परा रही हैं। यहां के गांवों में घर-घर में सैनिक होता हैं। सेना के प्रति यहां के लगाव के कारण अंग्रेजों ने यहां एक सैनिक छावनी की स्थापना कर 'शेखावाटी ब्रिगेड 'का गठन किया था। देश रक्षा के लिये सेना में शहादत देना राजस्थान की परम्परा रही है। झुंझुनू जिले के वीर जवानों को उनके शौर्यपूर्ण कारनामों के लिये समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न अलंकरणों से नवाजा जाता रहा हैं। अब तक इस जिले के कुल 130 से अधिक सैनिकों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जो पूरे देश में किसी एक जिले के सर्वाधिक हैं।

भारतीय सेना में योगदान के लिये झुंझुनू जिले का देश में अव्वल नम्बर हैं। वर्तमान में इस जिले के 55 हजार जवान सेना में कार्यरत हैं। वहीं जिले में करीबन 60 हजार भूतपूर्व सैनिक व अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। आजादी के बाद भारतीय सेना की और से राष्ट्र की सीमा की रक्षा करते हुये यहां के 486 जवान शहीद हो चुके हैं। जो पूरे देश में किसी एक जिले से सर्वाधिक है। कारगिल युद्ध के दौरान पूरे देश में 527 जवान शहीद हुये थे जिनमें यहां के 19 सैनिक शहीद हुये थे जो पूरे देश में किसी एक जिले से शहादत देने वालों में सर्वाधिक जवान थे। झुंझुनू जिले से अब तक 486 से अधिक सैनिक जवान सीमा पर शहीद हो चुके हैं।

यहां के गांवों में लोकदेवताओं की तरह पूजे जाने वाले शहीदों के स्मारक इस परम्परा के प्रतीक हैं। इस जिले के वीरों ने बहादुरी का जो इतिहास रचा है उसी का परिणाम है कि भारतीय सैन्य बल में उच्च पदों पर सम्पूर्ण राजस्थान की ओर से झुंझुनू जिले का ही वर्चस्व रहा है। इस क्षेत्र के सैनिकों ने भारतीय सेना में रहकर विभिन्न युद्धों में बहादुरी एवं शौर्य की बदौलत जो वीरता पदक प्राप्त किये हैं वे किसी भी एक जिले के लिये प्रतिष्ठा एवं गौरव का विषय हो सकता हैं। सीमा युद्ध के अलावा जिले के बहादुर सैनिकों ने देश मे आंतरिक शान्ति स्थापित करने में भी सदैव विशेष भूमिका निभाई हैं। सीमा संघर्ष एवं नागा होस्टीलीटीज हो या आपरेशन ब्लूस्टार या श्रीलंका सरकार की मदद हेतु किये गये आपरेशन पवन अथवा कश्मीर में चलाया गया आतंकवादी अभियान रक्षक या कारगिल युद्ध। सभी अभियान में यहां के सैनिकों ने शहादत देकर जिले का मान बढ़ाया हैं।

झुंझुनू जिले के हवलदार मेजर पीरूसिंह शेखावत को 1948 के युद्ध में वीरता के लिये देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। परमवीर चक्र पाने वाले पीरूसिंह शेखावत देश के दूसरे व राजस्थान के पहले सैनिक थे। यहां के सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी बढ़चढ़ कर भाग लिया था। आज भी यहां द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सरकार से पेंशन मिल रही है।

यहां के जवानो ने सेना के सर्वोच्च पदों तक पहुंच कर अपनी प्रतीभा का प्रदर्शन किया है। इस जिले के चित्तोसा गांव के एडमिरल विजय सिंह शेखावत भारतीय नो सेना के अध्यक्ष रह चुकें है। वहीं स्व. कुन्दन सिंह शेखावत थल सेना में लेफ्टिनेन्ट जनरल व भारत सरकार के रक्षा सचिव रह चुके हैं। जे.पी.नेहरा, सत्यपाल कटेवा, लेफ्टिनेंट जनरल केके रेप्सवाल सेना में लेफ्टिनेन्ट जनरल पद से सेवानिवृत हुये हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेप्सवाल सेना सेवा कोर में कार्यरत हैं। इसके अलावा यहां के काफी लोग सेना में मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। देश में झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला हैं जहां सैनिक छावनी नहीं होने के उपरान्त भी गत पचास वर्षो से अधिक समय से सेना भर्ती कार्यालय कार्यरत है। जिससे यहां के काफी युवकों को सेना में भर्ती होने का मौका मिल पाता है।

जिले में इतने अधिक लोगों का सेना से जुड़ाव होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा सैनिक परिवारों की बेहतरी व सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। कारगिल युद्ध के समय सरकार द्वारा घोषित पैकेज में यह बात भी शामिल थी कि हर शहीद के नाम पर उनके गांव में किसी स्कूल का नामकरण किया जायेगा मगर जिले के ऐसे कई शहीदों के नाम पर अब तक सरकार ने स्कूलों का नामकरण कई नहीं किया है।

झुंझुनू जिले के दोरासर गांव में सैनिक स्कूल प्रारम्भ हो चुकी है जिसका लाभ सेना में जाने वाले यहां के युवाओं को मिलेगा। 19 साल पहले हमने करगिल तो जीत लिया था, लेकिन शहीदों के परिवारों के सामने आज भी समस्याओं के कई करगिल खड़े हैं। जिन पर जीत दर्ज करनी अभी बाकी हैं। सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को देश का सैनिक जिला घोषित कर यहां के सैनिक परिवारों को सुविधायें उपलब्ध करवाने की तरफ पर्याप्त ध्यान दे तो आज भी झुंझुनू क्षेत्र से अनेक पीरूसिंह पैदा होकर देश के लिये प्राण न्योछावर कर सकते हैं। झुंझुनू जिले के सैनिको की बहादुरी देखकर कवि ने अपनी रचना में भी झुंझुनू के वीरो का गुणगान इस प्रकार किया है।

शुरा निपजे झुंझुनू, लिया कफन का साथ ।
रण-भूमि का लाडला, प्राण हथेली हाथ ।।

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

'यूं होता तो क्या होता'

यूं होता कि दुनिया के लोग पृथ्वी पर बसे लाखों गांवों में अपनी-अपनी छोटी-सी पंचायत चुनकर धरती-हवा-पानी-आग और बोली की हिफ़ाजत करते हुए अपनी गृहस्थी को सबके मिले-जुले स्वर और साधनों के बीच बसाये रखते। अपने गुजर-बसर की प्राकृतिक स्थानीय कला को पहचानकर लोकगीत गाते हुए अपने हिस्से की फसल काटते और अपनी-अपनी चदरिया बुनकर आपसी खुशहाली का इंतजाम कर लेते। उस चदरिया को अगली पीढ़ी के लिए ज्यों की त्यों छोड़कर संसार से बिदा होते रहते तो क्या होता?

यूं होता कि दुनिया के लोग अपने-अपने हाथ-पांव की सीमा में जीवन के लिए ज़रूरी मेहनत को ठीक से पहचान लेते तो प्रविधि और उधार के विषयों में आसक्त न होते। वे अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करते तो उनकी कामनाएं भी संतुलित बनी रहतीं और अपने आपको भूलकर जीने से बचे रहते तो क्या होता?

यूं होता कि दुनिया के लोग अपने-अपने स्वभाव को पहचान लेते और भली प्रकार समझ जाते कि दुनिया में ऐसे कोई प्रभु नहीं हैं जो हमारे कर्मों और उनके फलों का निर्धारण करते हों। तो वे खुद ही जान जाते कि सब अपने-अपने स्वभाव के प्रवर्तक हैं और एक-दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं। सब अपनी ज़रूरत का ही सामान जुटाते और बाकी सबके लिए छोड़ देते। अगर सब स्वनिर्भर होकर एक-दूसरे का प्रेम ही पाते तो क्या होता?

यूं होता कि दुनिया के लोग जाति, नस्ल, काले-गोरे और मज़हबी भेदभाव की खाई को पाटने के लिए एक सम्यक नागरिक बोध में रंग पाते और इस अहसास से भर उठते कि पृथ्वी पर सबके तन की माटी एक-दूसरे में मिली हुई है और सबके प्राणों का एक ही रंग है तो क्या होता?

मिर्ज़ा ग़ालिब याद आ रहे हैं...

हुई मुद्दत कि ग़ालिब मर गया पर याद आता है... वो हर इक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता

आवारा घूम रहे सांड ने युवक पर किया हमला

बैतूल। शहर के प्रमुख मार्गो और वार्डो में आवारा मवेशियों की धमा चौकड़ी देखने को मिल रही है। यह आवारा मवेशी अब राह चलते लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला

वीडियो शहर के कृष्णपुरा वार्ड टिकरी का सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कृष्णपुरा वार्ड निवासी अजय मालवीय सड़क से पैदल जा रहे थे तभी एक आवारा सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। अजय सड़क मार्ग से पैदल जा रहे है उन पर सांड अचानक हमला कर उन्हें जमीन पर पटक देता है। काफी देर तक भी जमीन पर ही पड़े रहते हैं। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया गया। नगर पालिका आवारा मवेशियों की धर पकड़ नहीं कर रही है। वार्ड में घूम रहे आवारा लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर रहे हैं। बारिश के दिनों मैं सड़कों पर भी आवारा मवेशियों का जमघट लगा रहता है जिसे हाथ से होते रहते है।

अभिनव को मिली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि

सन एट सेन यूनिवर्सिटी ताइवान में बतौर वैज्ञानिक कर रहे कार्य

बैतूल। मप्र विद्युत वितरण कम्पनी से सेवानिवृत्त राजेन्द्र सिंह परिहार एवं नमिता परिहार के सुपुत्र अभिनव सिंह परिहार ने आई आई टी इंदौर से पी एच डी की उपाधि प्राप्त कर जिले वासियों सहित अपने माता पिता एवं परिवार का नाम रोशन किया है। आईआईटी इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें डिग्री सौंप कर सम्मानित किया गया। अभिनव ने हाई स्कूल की परीक्षाएं उत्कृष्ट अंकों से पास कर रायपुर से बीटेक ट्रिपल आईटी किया। ततपश्चात राजगढ़ जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 साल लेक्चरर शिप करने के बाद आईआईटी इंदौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है, जिसमें उनका शोध वायरलेस कम्युनिकेशन पर केंद्रित था।

वर्तमान में अभिनव ताइवान में नेशनल सन एट सेन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। निश्चित ही अभिनव ने अपने परिवार के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। अभिनव की इस उपलब्धि पर परिवार जनों के अलावा सभी इष्टमित्रों रिश्तेदारों ने बधाई प्रेषित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

गांव से मुख्य सड़क तक रास्ता खराब था

बैलगाड़ी में गर्भवती महिला को एंबुलेंस तक लाया गया, एंबुलेंस में हुई डिलीवरी

बैतूल। जिले के शाहपुर ब्लॉक के धांसई गांव में सड़क नही होने की वजह से गांव तक एंबुलेंस नही पंहुच पाई जिसकी वजह से गांव की एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से एंबुलेंस तक लाना पड़ा इसी दौरान महिला की डिलेवरी एंबुलेंस में ही हो गई। बताया जा रहा है की धांसई गांव के संतलाल उइके की पत्नी ललिता उइके को गुरुवार सुबह से प्रसव

पीड़ा हो रही थी जिसके बाद उन्होंने 108 एंबुलेंस को फोन किया लेकिन गांव की सड़क बहुत खराब होने की वजह से एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई थी स जिसके बाद परिजनों ने ललिता उइके को बैल गाड़ी में बिठाकर करीब डेढ़ किलोमीटर मुख्य सड़क तक लाया गया जंहा 108 एंबुलेंस खड़ी हुई थी इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ गया और एंबुलेंस की टेक्निकल टीम ने महिला की डिलेवरी एंबुलेंस में ही कराई स डिलेवरी के बाद एंबुलेंस जच्चा बच्चा दोनो को शाहपुर सामुदायिक केंद्र लाया गया जंहा दोनो को भर्ती कराया गया डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा स्वाथ्य बताए है।

ख्वाब थे चमचमाती सड़क के यहां कीचड़ से लथपथ होकर करना पड़ रहा सफर

बैतूल। बैतूल से मलकापुर तक 7 किलोमीटर की 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई जा रही है। आठ महीने पहले ठेकेदार ने पुरानी सड़क उखाड़कर नई सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। लगभग 2 किलोमीटर डामर डालने के बाद बाकी बची सड़क पर सिर्फ गिट्टी और मुरम बिछाकर काम बंद कर दिया है। जिससे अब लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

आधी-अधूरी बनी सड़क में बारिश होने से और भी स्थिति खराब हो गई है। ठेकेदार के रवैए से ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली बच्चे, व्यापारियों के अलावा सभी वर्ग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण विजय ने बताया कि बरसात के पूर्व न बनाने की स्थिति में ठेकेदार ने पूरी सड़क को खोदना ही नहीं था। अब पूरे मार्ग पर मुरम बिछी है जिससे स्थिति बहुत ही खराब हो गई रोजाना इसमें लोग गिरकर घायल हो

रहे हैं। ग्रामीण राजेश का कहना है कि सांसद दुर्गादास उइके ने मार्ग का भूमि पूजन किया था। अब वे केंद्र सरकार में मंत्री है। उन्होंने अपने पुराने कार्यकाल में किए वादे और भूमि पूजन की भी नितांत चिंता करना चाहिए ताकि जनता उन पर विश्वास बनाए रखें।

ठेकेदार की मनमानी से परेशान– ग्रामीण मनीष ने बताया कि सड़क का हाल बहुत बुरा हो गया है। ठेकेदार अपनी मनमानी, जनप्रतिनिधि क्षेत्र की उपेक्षा और अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इस रबड़ी वाली सड़क से कोई भी जाना नहीं चाहता है अगर भाग्यवश कोई गया तो इस कीचड़ में गिरकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इस सड़क को बनाने में आठ महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इस मार्ग पर केवल मुरम डाल कर छोड़ दिया गया है। इस निर्माणाधीन सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे है वही स्कूल बच्चों का ड्रेस खराब हो जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों के अलावा राहगीर भुगतने को विवश है।

नहीं हो रही कोई मॉनिटरिंग– भारत 15 अगस्त को अपना 77 वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा मगर गांव के विकास की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्राम्य भारत अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। एक दर्जन गांवों के ग्रामीण इस बदहाल मार्ग से प्रतिदिन गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्या के प्रति कतई गंभीर नहीं है। स्थिति यह है कि वर्तमान में पदस्थ अधिकारी तो पूरे मामले से आज भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर लापरवाही बरत रहे हैं। इस सड़क की मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। जिस कारण ठेकेदार के कारिंदे सही काम नहीं कर रहे हैं।

इस दिन हुई थी शुरूआत– 19 अक्टूबर 2023 को बैतूल-मलकापुर-बरसाली मार्ग 7 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क के कार्य का शुभारंभ हुआ था। उस दौरान सांसद ने कहा था सड़क की गुणवत्ता अच्छी होंगी। लेकिन ठेकेदार की मनमानी के

कारण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष इमला बाई जावलकर, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यों सहित मार्ग की समस्त पंचायतों के सरपंच, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहित दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ 18 मार्च 2023 को सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया था।

कारगिल दिवस विशेष

बैतूल की बेटियों का कारगिल से कच्चे धागों से बंधा पक्का नाता

बैतूल। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के साथ-साथ बैतूल का राष्ट्र रक्षा मिशन भी रजत जयंती मना रहा है सेना के जवानों की हौसला अफजाई करने के संकल्प की। इस वर्ष बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का राष्ट्र रक्षा मिशन दल 18 अगस्त की शाम को बाड़मेर पहुंचेगा और 35 सदस्यीय दल द्वारा 19 एवं 20 अगस्त को भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सैनिकों की कलाई पर तिरंगा राखियां बांधी जाएगी। इसके पहले प्रतिवर्ष की तरह कारगिल के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद जवानों के लिए 527 राखियां पोस्ट की जाएगी। साथ ही द्रास सेक्टर में व कारगिल विजय स्मारक पर तैनात मद्रास रेजीमेंट के जवानों के लिए भी राखियां पोस्ट की जाएगी।

2021 में कारगिल पहुंचा था राष्ट्र रक्षा मिशन– समिति अध्यक्ष गौरी पदम ने बताया कि वर्ष 2021 में राष्ट्र रक्षा मिशन के 17 सदस्यीय दल ने द्रास क्षेत्र में कारगिल विजय स्मारक में स्थापित कैप्टन विक्रम बतरा, ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव, राइफलमेन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पाण्डे, कैप्टन एन केंगुरुज, मेजर सोनम वान्गचुक, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मपानी आचार्य, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, नायक दिगेन्द्र कुमार की प्रतिमाओं सहित सभी 527 शहीदों को तिरंगा राखियां समर्पित की थी। उन्होंने बताया कि कारगिल के योद्धाओं से बैतूल का कच्चे धागे से पक्का नाता जुड़ गया है, जिसे हमेशा निभाया जाएगा। प्रतिवर्ष समिति कारगिल के शहीदों के प्रति कृतज्ञ भाव के साथ 527 राखियां समर्पित करेगी।

कारगिल विजय से ही शुरू हुआ था राष्ट्र रक्षा मिशन

बैतूल की बेटियों ने 24 वर्ष पहले गौरवान्वित पहल की शुरुआत की थी। देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिपल देश की अंतरराष्ट्रीय सरहदों पर तैनात सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए बैतूल की बेटियों ने रक्षाबंधन का अपना प्रिय त्योहार देश के सैनिकों के नाम कर दिया था। 24 वर्षों से यह संकल्प राष्ट्र रक्षा मिशन की टीम संस्था अध्यक्ष गौरी बालापुरे पदम के नेतृत्व में निभा रही है। एक ओर पूरा देश 26 जुलाई को कारगिल विजय की रजत जयंती मना रहा है वहीं दूसरी ओर बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति 19 अगस्त को सरहद पर रक्षाबंधन का रजत उत्सव मनाएगी। श्रीमती पदम बताती है कि पिछले 24 वर्षों में राष्ट्र रक्षा मिशन को कारगिल विजय स्मारक तक पहुंचने का भी अवसर मिला। यहां उन्होंने 527 शहीदों के स्मारक पर रक्षाबंधन के दिन राखी समर्पित की थी। कारगिल के शहीद स्मारक एवं यहां तैनात जवानों के लिए प्रतिवर्ष बैतूल से राखियां पोस्ट की जा रही है। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में सैनिकों की शहादत और देशवासियों की सेना के प्रति समर्पित भावना से प्रेरित होकर ही बैतूल से राष्ट्र रक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी।

शहीद भवन विजय स्मारक पर दी जाएगी श्रद्धांजलि

बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार 26 जुलाई को वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सुबह 11 बजे शहीद भवन स्थिति विजय स्मारक के सम्मुख पहुंचने का अनुरोध नागरिकों से किया है।

कलेक्टर ने ग्रीन स्टेट कॉलोनी के कॉलोनाइजरों पर एफआईआर करने के दिए निर्देश

परमिशन के बाद भी नहीं बुनियादी सुविधाएं

बैतूल। राजस्व और नगरीय निकायों के गठजोड़ से कॉलोनी काटने वालों के वारे-न्यारे हो रहे हैं। झूठे सपने दिखाकर प्लॉट बेचने के बाद कॉलोनाइजर्स का कोई अता-पता नहीं है। लोगों ने प्लॉट ले तो लिए लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं होने से काफी

परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल पहले बैतूल की ग्रीन स्टेट कॉलोनी के कॉलोनाइजरों द्वारा विकास की अनुमति तो ली थी लेकिन तय अवधि तीन वर्ष में विकास के कार्य ही नहीं कराए गए। अब बैतूल के तेज तर्रार और संवेदनशील कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने धोखाधड़ी करने वाले कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

मौके पर अमले के साथ पहुंचे कलेक्टर– अंबेडकर वार्ड टिकारी क्षेत्र में ग्रीन स्टेट कॉलोनी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं ही राजस्व, नपा के अमले को लेकर पहुंच गए। कॉलोनी में प्लाट और मकान बेचने के लिए कॉलोनाइजर के द्वारा जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, उसकी पोल खुल चुकी है। कॉलोनी में सिर्फ एक ही रोड ही बनाई गई है। इसके अलावा विकास के कोई कार्य ही नहीं किए गए। कलेक्टर ने मौके पर कॉलोनी के रहवासियों से चर्चा कर उनकी परेशानियों को जाना। रहवासियों से मनमानी राशि लेने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के मामले में कलेक्टर ने बेहद गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जांच पूरी करने के बाद कालोनाइजर्स पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश एडीएम और सीएमओ नगर पालिका को दिए।

कॉलोनी में नहीं हो रहा कोई काम– कलेक्टर को कालोनी के लोगों ने बताया कि यहां न तो सड़क का निर्माण हुआ है और न ही कम्युनिटी हॉल बनाया गया। यहां पर न ही कोई गार्डन है और न ही वैसा माहौल जो उन्हें चाहिए। कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के साथ ग्रीन स्टेट कालोनी का निरीक्षण कर लोगों से चर्चा की। उन्होंने मौके पर मौजूद नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया को कॉलोनी बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। फिलहाल, देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है?

भूमि घोटाला: 26 खातेदारों की जमीन हड़पकर लिया लाखों का ऋण, राजस्व रिकॉर्ड में की हेराफेरी

बैतूल। राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जिले के ग्राम बोरगांव में एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एसपी को सौंपे आवेदन में प्रार्थी बोन्द्रया पिता गोविंदा, भूमला, धीरज पिता रामू ने बताया अनावेदक दीपक कापसे ने अपने भाई गुलशन कापसे और मां आशा कापसे के साथ मिलकर 26 सह खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवा दिए और एच.डी.एफ.सी. बैंक से भारी ऋण प्राप्त कर लिया। इस घोटाले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के स्पष्ट संकेत मिले हैं।

ऐसे उजागर हुआ मामला– प्रार्थी बोन्द्रया पिता गोविंदा ने 15 जुलाई 2024 को खसरे की कॉपी निकाली, जिसमें पता चला कि दीपक कापसे ने सभी खसरे अपने नाम पर दर्ज करवा लिए हैं। इस भूमि की कुल लागत 8.34 करोड़ रुपये है और इसका कुल रकबा 31 एकड़ है। दीपक ने इस भूमि को एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बाबू चौक बैतूल में बंधक रखकर भारी ऋण लिया है। इस मामले की शिकायत आवेदको ने कलेक्टर, एसपी से की है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही एवं शाखा प्रबंधक को आवेदन सौंपकर उचित कार्यवाही करने का

आग्रह किया है। आवेदन में बताया कि दीपक कापसे ने राजस्व अमले के सहयोग से 26 सह खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवा दिए। इसके बाद, उन्होंने एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण प्राप्त किया और इस राशि से बोरगांव में डेयरी फार्म और पशुधन खरीदा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, उन्होंने भैंसदेही शहर में घर या प्लाट भी खरीदा है।

प्रार्थियों को मिली धमकियां– प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि दीपक कापसे और उनके भाई गुलशन कापसे ने उन्हें धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा, हमारे नाम हटाकर खुद के नाम दर्ज किए गए हैं। जब हमने पूछा, तो हमें धमकी दी गई कि अगर हम शिकायत करेंगे तो जान से मार दिया जाएगा। प्रार्थियों ने मांग की है कि दीपक कापसे और उनकी मां आशा कापसे के सभी बैंक खातों को जांच पूरी होने तक होल्ड किया जाए ताकि ऋण की राशि को वापस लिया जा सके। इसके साथ ही, राजस्व अमले के सभी सहयोगकर्ताओं की जांच कर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

पेंशनर बोले- अन्य राज्यों की तरह उम्र के साथ बढ़ाई जाए पेंशन

बैतूल। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा बैतूल ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर बैतूल को नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एक सैकड़ा से अधिक पेंशनर्स कर्मचारी भवन बैतूल में एकत्रित हुए और जनसभा में अपनी मांगों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इसके बाद रैली निकाल कर पेंशनर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे। पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में केंद्रीय तिथि से महंगाई राहत स्वीकृत करना, धारा 49/6 समाप्त करना और आयु वृद्धि के साथ अतिरिक्त पेंशन वृद्धि स्वीकृत करना शामिल हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर 65 वर्ष पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त पेंशन वृद्धि की मांग की है। पेंशनर्स ने आयुष्मान योजना का लाभ और निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की भी मांग की है। इसके अलावा, 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को बिना न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की तरह अविवाहित बेटी, विधवा और परित्यक्ता बेटी को आजीवन परिवार पेंशन स्वीकृत करने की मांग की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को शुरू सेवा तिथि से पूर्ण वेतनमान लागू करने और अर्जित

अवकाश प्रकरणों का नगदीकरण सुगमतापूर्वक करने की मांग की गई है। ज्ञापन में छठे और सातवें वेतनमान पुनरीक्षण के 27 और 32 माह के एरियर की अदायगी भी प्रमुख मांगों में शामिल हैं। जनसभा में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि यह सभी मांगें उनकी जीवनशैली को सुधारने और उनकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करेगी और उन्हें राहत प्रदान करेगी। मप्र सरकार पर पेंशनर्स ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के नारे को भूल चुकी है और पेंशनर्स की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और एमपी, एमएलए के वेतन भत्ते बिना मांग के बढ़ जाते हैं, वहीं पेंशनर्स को ज्ञापन सौंपकर महीनों इंतजार करना पड़ता है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मप्र के आह्वान पर पूरे मध्यप्रदेश के 55 जिलों और उनके समस्त ब्लॉक तथा तहसील शाखाओं में पेंशनर्स एसोसिएशन ने 9 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। पेंशनर्स का मानना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

डॉ. दीपेंद्र शर्मा दिल्ली जाएंगे

धार। भारत की मेजबानी में 46 वी विश्व विरासत समिति की मीटिंग 21 से 31 जुलाई तक मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में हो रही है। जिसका भव्यतम उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को किया है। इस महत्वपूर्ण इवेंट में विश्व के 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे है। धार से इंटेक नईदिल्ली की गव्हरनिंग कार्उंसिल के सदस्य व जिला कन्वेनर इंटेक धार, जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद के सदस्य व भोज शोध संस्थान के संस्थापक व निदेशक डॉ दीपेंद्र शर्मा इसमें गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए है। डॉ शर्मा 26 व 27 जुलाई को शामिल होंगे। धार जिले से वे एकमात्र आमंत्रित प्रतिनिधि होंगे।

रेल बजट में इन्दौर दाहोद को 600 करोड़ और छोटा उदयपुर- धार को 350 करोड़ मंजूर किए

रेल लाओ महासमिति ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार माना

धार। सबका साथ सबका विकास नारे को सार्थक करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धार - झबुआ के चहुमुखी विकास के लिए रेल बजट में इंदौर दाहोद को 600 करोड़ और छोटा उदयपुर धार को 350 करोड़ रुपए आवंटन कर अंतरिम बजट में घोषित राशि में कोई बदलाव नहीं किया। इंदौर -दाहोद और छोटा उदयपुर - धार रेल परियोजना का पिछले एक वर्ष से तेज गति से कार्य चल रहा है। क्षेत्र की वर्षो पुरानी मांग सन 2025 में पूरी होने वाली है और रेल पटरी पर दौड़ेगी प्रधानमंत्री ने चांद से तारे तोड़कर लाने वाला काम जो किया है उसके लिए क्षेत्र की जनता में अपार हर्ष और उल्लास है। इंदौर दाहोद एवं छोटा उदयपुर - धार रेल लाओ महा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष पवन जैन गंगवाल और नरेश राजपुरोहित प्रवीण टाक, शांतिलाल शर्मा, आशीष वैद्य, विनीत खत्री ,कमल हरोड़ , इंदर सिंह ठाकुर , पियूष जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य मंत्री मोहन यादव , केंद्रीय राज्य मंत्री, धार सांसद सावित्री ठाकुर, इंदौर सांसद शंकर लालवानी , झाबुआ सांसद अनिता चौहान को धार झाबुआ की जनता आभार मानकर बधाई दी अब 2025 में धार झाबुआ में रेल दौड़ कर ही रहेगी।

राम रहीम रोटी बैंक के सहयोगी बने सब्जी विक्रेता

सुबह सवेरे सोहागपुर। राम रहीम रोटी बैंक सामाजिक संस्था विगत करीबन 10 सालों से प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंद, बेघर, बेसहारा लोगों एवं नर्मदा परिक्रमावासियों को भोजन कराने का पुण्य एवं सराहनीय कार्य करती आ रही है। उक्त पुण्य कार्य में नगर , ग्रामीण क्षेत्र एवं बाहर से भी सेवाभावी व्यक्ति मदद प्रदान करते रहते हैं। राम रहीम रोटी के सदस्य पार्षद जमील खान ने बताया कि राम रहीम रोटी बैंक में कोई नगद राशि के रूप में तो कोई खाद्यान्न के रूप में सहायता करता है। लम्बे समय से अल्वी बाबा परिवार, दर्शन सिंह मौर्य एवं घनश्याम मामू की स्मृति में इनके परिजन प्रतिमाह जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। इसी तारतम्य में अब नगर की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता अफसर खान , तुलसीराम साहू, कामता प्रसाद के अलावा फुटकर सब्जी विक्रेता कमलेश कहार, फतेह कुशवाहा, नर्मदा प्रसाद कहार भी जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था हेतु सप्ताह में एक-एक दिन अपना योगदान दे रहे हैं।

कलेक्टर ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने गुरूवार को आंगनबाड़ी केन्द्र सिंहपुरबड़ा का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद कर आवश्यक जानकारी ली और यहाँ की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती पटले ने आंगनबाड़ी केन्द्र में मौजूद बच्चों से संवाद के दौरान मीनू के अनुसार मिलने वाले नाश्ते व भोजन के बारे में पूछा। बच्चों को आज दिये गये नाश्ते एवं भोजन का सैंपल भी चेक किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कविता भी सुनी और उन्हें दुलार किया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए यहां दर्ज बच्चों, उपस्थित बच्चों और प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों की जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लाड़ली बालिकाओं की ई- केवायसी एवं डीबीटी की जानकारी ली। गर्भवती व धात्री महिलाओं की आभा आर्डडी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों की भी आभा आईडी बनाई जाये। यहाँ मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विभागीय मोबाइल एप सम्पर्क एवं पोषण ट्रैकर की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर श्री शुभम कुमार यादव, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती मोहिनी जाधव सहित महिला बाल विकास विभाग का अमला मौजूद था।

मंत्री श्री सिंह 26 एवं 27 जुलाई को जिले के प्रवास पर

नरसिंहपुर। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह शुक्रवार 26 जुलाई व शनिवार 27 जुलाई को जिले के प्रवास पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार मंत्री श्री सिंह शुक्रवार 26 जुलाई को प्रातः 8 बजे गाडरवारा के पलोटनगंज में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित मेराथन दौड़ में भाग लेंगे। इसके बाद यहां उनका समय आरक्षित रखा गया है। इसके पश्चात दोपहर दो बजे सालीचौका में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात रात्रि 8 बजे लोलरी आयेंगे। यहां उनका समय आरक्षित रखा गया है और यहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्री श्री सिंह शनिवार 27 जुलाई को प्रातः 11 बजे ग्राम लोलरी से गाडरवारा के लिए प्रस्थान करेंगे।

राजस्व महा अभियान 2.0 , 31 अगस्त तक जारी है,इसका लाभ अवश्य लेवें,ग्राम छटिया में ग्रामीणों से बोले कलेक्टर

राजस्व अभियान अंतर्गत किया गया शिविर का निरीक्षण

धार। राज्य शासन द्वारा 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। आप सभी इसका लाभ अवश्य लेवें और अपने राजस्व प्रकरणों का निराकरण करवाएं। यह बात कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज धार तहसील के ग्राम छटिया में ग्रामीणों से चर्चा में कही।

कलेक्टर श्री मिश्रा आज राजस्व अभियान अंतर्गत धार तहसील के ग्राम और छटिया और आहू के भ्रमण पर रहें। एसडीएम रोशनी पाटीदार साथ मौजूद रही। कलेक्टर श्री मिश्रा सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कार्यालय आहू में जारी शिविर में पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूद पटवारी से बी - 1 के वाचन के सम्बंध में जानकारी ली और शिविर में ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर इसके पश्चात ग्राम छटिया में खाटला बैठक आयोजित कर ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा को शासन द्वारा जारी इस अभियान में आप अपना नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, समग्र-ईकेवायसी, नक्शा तरमीम से संबंधित कार्य करवा सकते है। साथ ही आप सभी पटवारी द्वारा किए जा रहे बी-1 के वाचन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे तथा जो भूस्वामी मृत हो गए है, उनके नाम हटाकर उनके वारिस का नाम जुड़वाए। साथ ही भूमि से संबंधित जो भी कार्य पेंडिंग है, उन्हे पूर्ण करा ले। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि आप बी-1 के वाचन को ध्यान से सुने एवं नाम हटाने तथा जुड़वाने की प्रक्रिया अभियान के दौरान पूर्ण करवाएं। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि वे पंचायत में आए तो ईकेवायसी हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं मोबाईल लेकर आए, क्योंकि दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही ईकेवायसी का कार्य पूर्ण होता है।

आंगनवाड़ी , सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल आयुक्त सिद्दीकी से मिला

सुबह सवेरे सोहागपुर।

आंगनवाड़ी एवं सहायिका मिनी कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त सोफिया सिद्दीकी फारुकी से संचनालय में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा अहिरवार ने किया। आपने आयुक्त सोफिया सिद्दीकी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं के समस्याओं से बिन्दु बार अवगत कराया। आयुक्त ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। आयुक्त सोफिया सिद्दीकी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संपर्क एप से किसी भी सहायिका को डरने की आवश्यकता नहीं है।एप के कारण किसी का भी मानदेय नहीं काटा जाएगा। उक्त एप इस कारण प्रारंभ किया गया है। जहां आंगनवाड़ी खोली ही नहीं जाती। खाना, नाश्ता सही समय पर नहीं मिलता।या दबाव डालकर हाजरी लगवाई जाती है। यह एप निगरानी के लिए लागू किया गया है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समय मुख्य कार्यकर्ता के समय से अलग है। वाकई उनकी बहुत समस्याएं हैं जल्द से मिनी केंद्रों को मुख्य केंद्र में परिवर्तित कराया जाएगा। तथा वहां भी सहायिका की नियुक्ति की जाएगी। उक्त

कार्य नवंबर दिसंबर तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

आपने आगे कहा कि सहायिका का मानदेय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रतिमाह डलवाने के निर्देश समस्त डीपीओ को कर दिए हैं। आदि समस्याओं के मामले में सकारात्मक कदम उठाए जाने की बातें कहीं हैं। उक्त आश्य की जानकारी प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष सुमित्रा अहिरवार ने सुबह सवेरे संवाददाता को दी। प्रदेश आंगनवाड़ी अध्यक्ष सुमित्रा अहिरवार ने सभी समस्याओं पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

राजस्व मामलों का समय पर हो निपटारा: जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर ने ली मुलताई पट्टन क्षेत्र के पटवारियों की बैठक

बैतूल। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मुलताई पहुंचकर तहसील कार्यालय मे संयुक्त रूप से प्रभात पट्टन एवम मुलताई के पटवारियों की बैठक ली जिसमें राजस्व सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों का समय सीमा में निपटारा करने का कहा। जिला कलेक्टर ने राजस्व महा अभियान के संदर्भ में भी पटवारी से चर्चा की। अभियान में क्या समस्या है, कार्य में क्या दिक्कत आ रही है, उसके संदर्भ में उनसे जानकारी ली। इसी के साथ समय पर रिकॉर्ड अपडेशन करने संबंधी निर्देश दिए गए। किसानों का पीएम सम्मान, समग्र आधार ई केवाईसी, एनपीसीआई रिकॉर्ड अपडेशन एवं राजस्व संबंधी शिकायत शामिल है। सभी प्रकरण समय सीमा में अभियान के दौरान शत प्रतिशत निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में एसडीएम मुलताई जनपद सीईओ प्रभात पट्टन और मुलताई तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं समस्त पटवारी उपस्थित रहे।

पुलिस ने 7 गौ वंश तस्करी करते दो आरोपियों को किया गिरफ्तार , पारसडोह गौशाला पहुंचाए गौ वंश

बैतूल। साईखेड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी कर रहे आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 7 नग गौ वंश को प्रभात पट्टन क्षेत्र के पारसडोह स्थित गौशाला पहुंचाया। पूरा जानकारी के अनुसार कुंवरलाल पुत्र बारिकराम साकरे उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम हिवरखेड महाराष्ट्र का होना बताया एवं भागे हुये व्यक्ति का नाम पता

पुछने पर स्वयं का पुत्र गणेश होना बताया। दोनो के द्वारा गौवंश को कत्लखाना महाराष्ट्र ले जाना बताया, जो आरोपियो का कृत्य अपराध धारा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी कुंवरलाल साकरे से 7 नग गौवंश एवं गौवंश के गले मे बंधी रस्सियां एवं हाकनें की लकड़ी एवं मोटरसाईकल क्रमांक MH 27DD9894 जप्त किये गये एवं जप्त किये गौवशं को गौशाला पारसडोह पंहुचाया।

दलदल में तब्दील हुआ मासोद बायपास मार्ग

मुख्य मार्ग से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

बैतूल/मुलताई। मुनगर के मध्य से गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन का दबाव कम हो सके इसके लिए मार्ग के दोनों ओर सूचना पटल लगाकर भारी वाहनों का मुख्य मार्ग से प्रवेश निषेध कर दिया गया। किंतु जिस बाईपास मार्ग से यात्री बसों का और वाहनों का गुजर हो रहा है वहां रोड खोजना कठिन है सड़क मे बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। नई व्यवस्था के तहत अब नागपुर की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन एवं यात्री बस अमरावती रोड होते हुए सिंचाई विभाग के पास से बने बाईपास से होकर बस स्टैंड पहुंच रही है। नगर वासी लंबे समय से प्रशासन से नगर के मुख्य मार्ग से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। भारी वाहनों का मासोद रोड होते हुए बाईपास किया जाना प्रशासन का सराहनीय कदम है। किंतु जिस बाईपास से भारी वाहन और यात्री बस गुजर कर बस स्टैंड पहुंच रहे है। वहा मार्ग खोजना कठिन है संपूर्ण बाईपास मार्ग गड्ढे और दलदल से पट गया है बरसात का पानी गढ्ढों में भर जाने के कारण यह अनुमान लगाना कठिन है कि गड्ढे कितने गहरे है। ट्रैफिक को बाईपास करने से मुख्य मार्ग की समस्या का तो हल हो गया है किंतु यात्री बसों और भारी वाहनों की समस्या प्रारंभ हो गई

है । बस संचालक बताते हैं कि यात्री बसों का इस बाय पास से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। मुख्य मार्ग से भारी वाहनों का प्रबंध सराहनीय प्रयास अवश्य है किंतु जिस मार्ग से बाईपास किया जा रहा है उस मार्ग का सुधार कार्य भी किया जाना चाहिए ।

12 साल पहले बनाया था नगर पालिका ने बायपास मार्ग- मुलताई मासोद रोड होते हुए खाटू श्याम मंदिर के सामने से सिंचाई विभाग के पास अमरावती रोड से मिलने वाले बायपास मार्ग का निर्माण कार्य नगर पालिका ने आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व जी.ए .बरस्कर के अध्यक्ष के कार्यकाल में बनाया था । इस बाईपास मार्ग के निर्माणाधिन काल में ही ही मार्ग की गुणवता को लेकर सवाल उठने लगे थे इसके बाद अनेकों बार नगर वासी इस मार्ग के सुधार कार्य की मांग करते रहे हैं जिसका कोई हल नहीं निकला। जानकार बताते हैं कि हाल ही में फिर नगरपालिका इस मार्ग के निर्माण की योजना बना रही है अब यह देखना रोचक होगा कि निर्माण कार्य के बाद यह मार्ग कितना सुरक्षित हो पता है। किंतु नागरिकों का मानना है कि इससे पहले की मार्ग निर्माण हो सड़क के मध्य बने बड़े-बड़े गड्ढों का सुधार कार्य किया जाना चाहिए।

इनका कहना

कायाकल्प 1.0 योजना मे उक्त बाईपास मार्ग निर्माण कार्य भी शामिल है । जिसकी निविदा जारी कर दी गई है। आगामी माह में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

- योगेश अनेराव
उपयंत्री नगर पालिका मुलताई

वीर शहीदों के सम्मान में युवा मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस

वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें युवा : प्रियांक

नरसिंहपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला नरसिंहपुर द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मशाल जुलुस का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियांक जैन के नेतृत्व मे किया गया , मशाल जुलुस स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर सुभाष पार्क मे संपन्न हुआ, जिसमे महापुरुषों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने कहा कि शहीदों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता इस आजादी को पाने के लिए जाने कितने शहीदों ने अपना प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें अपने देश की विशेषताओं को कायम रखते हुए सहेजना होगा। जब जब देश पर हमला हुआ तब तब हमारे वीर जबानो ने उसका कड़ा जवाब दिया, युवाओं को वीर जवानो के जीवन से प्रेरणा लेने की जरुरत है, भाजपा जिला महामंत्री डा हरगोबिंद पटेल ने कहा कि देश के जवान किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं, चिलचिलाती गर्मी, मूसलाधार बारिश, जमा देने वाली ठंड में घर-परिवार से

दूर सैनिक अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। वीर जवानों के कारण ही हम और हमारा परिवार, समाज चैन की साँस लेता हैं, वे हैं इसलिए हम हैं। भाजयुमो जिलाध्यक्ष प्रियांक जैन ने कहा कि कारगिल की लड़ाई मां भारती के वीर सपूतों के शौर्य का प्रतीक है. भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण का मैं हृदय से वंदन करता हूं.आज का दिन हमारे सैनिकों की वीरता और पराक्रम की कहानियों से भावी पीढ़ियों को देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मै सभी युवाओं से आग्रह करता हु देश के वीर शहीदों के जीवन को आत्मसात करें, और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए इस लिए उनकी गाथाये नौजवानों तक ले जाये, और नौजवानों को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करें, उक्ताशय की जानकारी देते हुए युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रखर दुबे ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा के जिला महामंत्री चौधरी अभिषेक रघुवंशी, आभार मंडल अध्यक्ष शिवम श्रीवास्तव ने किया,कार्यक्रम मे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महंत प्रीतम पुरी गोस्वामी,भाजपा के जिला महामंत्री ठाकुर राजीव सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा, जिला सह कार्यालय मंत्री शिशिर दुबे,सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत श्रीवास्तव,राजेंद्र ठाकुर, अंशुल नेमा, महिला मोर्चा से रेखा पटेल, बबीता जाट, शक्ति बागरी, युवा मोर्चा से मनोज ठाकुर, नीलेश पटेल, सिद्धार्थ पटेल, नीरज कुशवाहा, श्रीकांत राय,आशीष राजपूत, अंकेश अग्रवाल, नीरज दुबे, श्रेयांश ताम्रकार, योगेश नौरिया, वीरेंद्र पटेल,उदित शर्मा,रचित चौरसिया, अंकित खत्री, गौरव तिवारी, लखन गुमास्ता, सहित कार्यकर्ता उपस्तिथ रहे।

कलेक्टर ने किया मूंग उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने मूंग उपार्जन केन्द्र पटेल वेयरहाउस मगरधा, उपार्जित सेवा सहकारी समिति लौकीपार का गुरूवार को आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थायें देखी और किसानों से चर्चा भी की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मूंग बेचने आये किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने यहां सर्वेयर से किसान द्वारा लाये मूंग का परीक्षण कराया, जो मानक स्तर

की पाई गई। निरीक्षण के दौरान समिति में बारदानो की पर्याप्त उपलब्धता पायी गई। इसी तरह कलेक्टर ने वेयरहाउस करेली बस्ती देव वेयरहाउस कनवास और चौधरी वेयरहाउस का निरीक्षण किया। सभी जगह पर्याप्त बारदाने एवं मानक स्तर की मूंग उपार्जन करना पाया गया।निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर श्री शुभम कुमार यादव, उप संचालक कृषि श्री उमेश कुमार कटहरे, जिला विपणन अधिकारी श्री मन्नू लाल कुसरे, उपायुक्त सहकारिता श्री राजेन्द्र सिंह, जिला प्रबंधक वेयरहाउस श्री आकाश तिवारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

सत्ता का सर्कस

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

बेरोजगारी बढ़ रही है भले ही सरकार इसे छुपाना चाहे

देश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। सरकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। पुरानी कांग्रेस की सरकार का रवैया भी इसी तरह का होता था। अब बदलाव सिर्फ इतना आया है कि सरकार इस सच को दबाने के लिए अपनी तमाम एजेंसियों को लगा देती है। रिजर्व बैंक भी आंकड़ों के जरिए इस सच पर पर्दा डालने की कोशिश करता है कि देश में उपलब्ध रोजगार से ज्यादा बेरोजगार लोगों की संख्या है। चुनाव में भी रोजगार के मुद्दे का वो असर नहीं दिखता जो सत्तर-अस्सी के दशक की राजनीति में देखने को मिलता था। इसकी वजह मुद्दे को नेतृत्व देने वाले चेहरे की कमी भी हो सकती है। आज की राजनीति बेरोजगारी पर धर्म हावी होता दिख रहा है। धर्म की राजनीति के चलते ही भाजपा अपनी सरकार बचाए हुए है। बेरोजगारी की जिस तस्वीर को नरेन्द्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार छुपाती रही वह मुंबई के कलिना में एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर देखने मिली। एयर इंडिया ने यूटिलिटी एजेंट के 1802 पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया था। जिसमें हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स नौकरी पाने के लिए पहुंच गए। करीब 15000 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। वहीं, एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड ने इनकी संख्या करीब 50 हजार बताई है। कई पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर भी थे। नौकरी पाने के लिए भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों को अपना सीवी जमा करके वहां से चले जाने को कहा। इसी तरह का एक घटनाक्रम कुछ दिन पहले गुजरात से सामने आया था। एक निजी फर्म में मात्र 10 पदों के लिए भर्ती अभियान के लिए लगभग 1,800 उम्मीदवार आए थे। इतनी भीड़ थी कि कार्यालय के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले रैंप पर लगी रेलिंग लोगों के वजन के कारण गिर गई। सौभाग्य से, रैंप बहुत ऊंचा नहीं था, और रेलिंग गिरने के बाद अपना संतुलन खोने वाले किसी भी उम्मीदवार को गंभीर चोट नहीं आई।

आंकड़ों में क्या है रोजगार की तस्वीर!

हाल ही में सिटी ग्रुप इंडिया ने भारत की अपने बढ़ते कार्यबल के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकरियां सृजित करने की क्षमता के मामले में चिंता जताई थी और एक प्रतिवेदन में कहा था कि भारत को आगामी दशक में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है, जबकि वह प्रतिवर्ष केवल अस्सी से नब्बे लाख नौकरियां ही सृजित करने की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी एक प्रतिवेदन जारी किया गया है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के मामले में 6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है और इस दौरान लगभग 4.7 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और देश में कार्य करने वाले नागरिकों की संख्या अब 64.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत की रही थी। अब कहां सिटी ग्रुप इंडिया की भारत में केवल 80-90 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होने की राह पर की बात की है और कहां भारतीय रिजर्व बैंक की भारत में 4.7 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की बात है, दोनों संस्थानों के आकलन में भारी अंतर दिखाई देता है। एक अन्य रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट की है। इसके मुताबिक देश की कामकाजी आबादी तेरह साल में तीन प्रतिशत बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है। यह 2036 तक 65 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। जून 2024 में बेरोजगारी दर पिछले आठ महीनों के उच्चतम स्तर 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने यह 7 प्रतिशत थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, यह जून 2023 में दर्ज 8.5 प्रतिशत से वृद्धि को दर्शाता है, जो उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के तहत समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। बेरोजगारी दर एक मीट्रिक है जो श्रम बल में सक्रिय रूप से रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को मापता है। जून 2024 में महिला बेरोजग़ारी दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा होकर 18.5 प्रतिशत पर पहुँच गई, जो पिछले साल के इसी महीने में 15.1 प्रतिशत थी। इस बीच, पुरुष बेरोजग़ारी दर पिछले साल की इसी अवधि के 7.7 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी ज़्यादा यानी 7.8 प्रतिशत रही। सीएमआईई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जहां बेरोजगारी दर मई 2024 के 6.3 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 9.3 प्रतिशत और जून 2023 में 8.8 प्रतिशत हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए यह दर मई के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 8.2 प्रतिशत हो जाएगी और महिलाओं के लिए यह दर इसी अवधि के 12.0 प्रतिशत से बढ़कर 17.1 प्रतिशत हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि देखी गई, जहां मई में 8.6 प्रतिशत से जून 2024 में दर बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में भी अधिक वृद्धि देखी गई (मई में 18.53 प्रतिशत की तुलना में जून 2024 में 21.36 प्रतिशत)।

यहां नौकरी लेकिन उम्मीदवार नहीं

फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (एफपीएसबी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्ण मिश्रा ने बुधवार को कहा कि देश में रोजगार पाने की काबिलियत की समस्या है क्योंकि लगभग 18 लाख नौकरियों को लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी अगले पांच साल में 1.5 लाख नौकरियां जेनरेट करेगा। अभी यहां करीब 6,000 कर्मचारी वित्तीय सेवा क्षेत्र में हैं। मिश्रा ने केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर कहा कि पिछले साल देश में वित्तीय सेवाओं में 46.86 लाख नौकरियां पैदा हुईं। इनमें से सिर्फ 27.5 लाख नौकरियां ही भरी गईं। इससे पता चलता है कि 18 लाख नौकरियों को लेने वाला कोई नहीं था। इसका कारण रोजगार हासिल करने की काबिलियत है बैंकों, बीमा कंपनियों, ब्रोकरेज हाउस और म्यूचुअल फंड कंपनियों को हमेशा ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। उपलब्ध प्रमाणित वित्तीय नियोजकों (सीएफपी) की संख्या की तुलना में लगभग 40 गुना अधिक नौकरियां हैं। एफपीएसबी इंडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लि.(एफपीएसबी लिमिटेड) की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी है। यह वित्तीय नियोजन पेशे के लिए वैश्विक मानक-निर्धारण से जुड़ा निकाय है। भारत में 2,731 प्रमाणित सीएफपी पेशेवर हैं जबकि पूरी दुनिया भर में इनकी संख्या 2.23 लाख है। भारत में 2030 तक लगभग 10,000 सीएफपी होंगे जबकि मांग के कारण जरूरत 1,00,000 की होगी।

आउटसोर्स से चल रहीं सरकारें

नौकरियों की जब बात होती है तो आज भी सरकारी क्षेत्र सबसे ज्यादा आकर्षक माना जाता है। लेकिन, पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने सीधी भर्ती करने के बजाए आउट सोर्स के जरिए सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। युवाओं को आउट सोर्स एजेंसी के जरिए मिली नौकरी में पूरा वेतन भी नहीं मिलता और कमीशन भी देना होता है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजकुमार कर्रहे का इस सिस्टम के बारे में दिया गया बयान महत्वपूर्ण है। राजकुमार कर्रहे के अनुसार मध्यप्रदेश में आउटसोर्स के जरिए हो रही भर्ती में फर्जीवाड़ा चल रहा है। गुजराती और राजस्थान की कंपनियों के जरिए सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कराई जा रही है। ये कंपनियां बेरोजगार नौजवानों से भर्ती के नाम पर दो-दो लाख लाख रुपए की मांग कर रही हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा से स्कूल, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई है। नियुक्ति के बाद भी 6 से आठ हजार रुपए काटते हैं।

महाराष्ट्र में लाड़ला भाई का मोदी मॉडल

सरकारों की रुचि रोजगार देने से ज्यादा लोक लुभावनी योजनाओं के जरिए चुनाव जीतने में रहती है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होना है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेश अपने बजट में महिलाओं के लिए जहां लाड़ली बहन योजना घोषित की है, वहीं अब युवाओं के लिए लाड़ला भाई योजना भी घोषित की है। इस योजना के तहत युवाओं को किसी कौशल में प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग के दौरान छह से 10 हजार रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों द्वारा भाजपा नीत केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया जाता रहा है। अब तीन महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति (भाजपा, शिवसेना, राकांपा) सरकार इस मुद्दे पर घिरने के बजाय आक्रामक रहना चाहती है। इसलिए उसके वित्त मंत्रालय के प्रभारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने इस वर्ष के बजट में जहां महिलाओं को लाड़ली बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की है, वहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र का निवासी प्रमाणपत्र रखने वाले बारहवीं पास युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए छह हजार रुपए, डिप्लोमा एवं आईटीआई करने वाले युवाओं को आठ हजार रुपए एवं स्नातक युवाओं को 10 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं को मिल सकेगा। योजना पर सरकार 5,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र सरकार की इस योजना की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार हमारी जरूरत है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है।

कर्नाटक में भी रोजगार पर घिरी सरकार

प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को सौ प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले से कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार विवाद में आ गई। विवाद बढ़ा तो 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली। दरअसल, सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए थे। कैबिनेट ने 16 जुलाई को बिल पास कर दिया। इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश करने की बात कही जा रही थी। हालांकि उससे पहले ही इस पर बड़ी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया है। कर्नाटक में 20 फीसदी गैर कन्नड़ आबादी काम करती है। बेंगलुरु की कंपनियों में गैर कन्नड़ कर्मचारियों की तादाद 35 फीसदी आंकी गई है। इनमें से अधिकतर उत्तर भारत, आंध्र और महाराष्ट्र से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, बेंगलुरु शहर की कुल आबादी का 50 फीसदी गैर कन्नड़ भाषी हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा की अनिवार्यता पर लंबी बहस भी छिड़ी थी, जिसके बाद हिंदी में नाम लिखे गए साइन बोर्ड तोड़े गए थे। विवादास्पद बिल के मुताबिक, योग्य स्थानीय कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हैं तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से 3 साल के अंदर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि इसमें एक शर्त ये भी जोड़ी गई है कि अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकती हैं। सरकार की नोडल एजेंसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेगी और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के कर्नाटक सरकार के फैसले से औद्योगिक घरानों ने नाखुशी जताई थी। उनका कहना था कि इस बिल से भेदभाव बढ़ेगा और इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। कर्नाटक पहले भी निजी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान कर चुका है। इनके अलावा हरियाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश, आंध्र और महाराष्ट्र भी ऐसी ही घोषणा की गई। ये राज्य निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का ऐलान भी कर चुके हैं, मगर किसी भी राज्य में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। ये सभी ऐलान कहीं कोर्ट में अटक गए हैं, तो कहीं इन पर काम नहीं हुआ। झारखंड सरकार ने कहा था कि जनवरी 2023 से निजी कंपनियों में 40 हजार तक की मासिक सैलरी वाले 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य होगा। 10 से ज्यादा कर्मियों वाली सब कंपनियों पर ये लागू होगा। उल्लंघन पर 5 लाख जुर्माना लगेगा। हरियाणा सरकार द्वारा निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, बाद में राहत दी। पर केस अब भी लंबित है।

अग्निवीर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश

लोकसभा चुनाव में भाजपा की चार सौ पार की रणनीति फेल होने की एक वजह अग्निवीर योजना को भी माना गया है। कांग्रेस ने चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस ने सरकार बनने पर योजना बंद करने की बात भी कही थी। अग्निवीर योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में नवाचार करने की कोशिश की है। योजना में चुने गए सैनिकों को वो लाभ नहीं मिल रहे जो नियमित नियुक्तियों में मिलते थे। सरकार अग्निवीर योजना वापस लेने के मूड में नहीं है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में दस में से सिर्फ पांच सीट ही भाजपा जीत पाई थी। विधानसभा चुनाव में अग्निदेव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब आरक्षण का दांव चला है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। अब से राज्य में इन पदों पर होने वाली सभी नई भर्तियों में यह आरक्षण लागू रहेगा। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्नि वीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी।

भोपाल में बारिश, 18 जिलों में अलर्ट

सागर में पगरा डैम के 5, टीकमगढ़ में बान सुजारा के सभी 12 गेट खोले

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में गुरुवार को भी कई जिलों में बारिश का दौरा जारी है। राजधानी भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश होती रही। दोपहर में तेज पानी गिरा। पन्ना में रात से बारिश जारी है, यहां के एनडीआरएफ और होमगार्ड कार्यालय में पानी भर गया है।

इससे पहले बुधवार को सागर में पगरा डैम के 11 में से 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। बीना के बिल्धव में लोगों को घरों की छतों से रेस्क्यू करना पड़ा। टीकमगढ़ में धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से बुधवार रात करीब 10 बजे बान सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोलकर 480 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया। देर रात बड़ागांव धसान में पुल पर 2 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा। निवाड़ी जिले में शाम को जामनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। यहां बने टापू पर 4 युवक फंस गए। पानी का बहाव ज्यादा होने से बचाने गए गोताखोर भी फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दतिया के सनकुआ धाम में युवक सिंध नदी में बह गया।

28 जुलाई से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम- सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक, मानसून ट्रफ ऊपर चली गई है। लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है। एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ गुजरात में है। यह मानसून ट्रफ के साथ मर्ज हो गया है। इन वजहों से प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि 28 जुलाई से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी हो सकती है। 29 और 30 जुलाई को उत्तरी हिस्से में तेज बारिश होने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ का प्रदर्शन

भोपाल पहुंचे सैंकड़ों शिक्षक, 3 दिन तक देंगे धरना

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश स्कूल अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को शाहजानी पार्क में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने यह प्रदर्शन अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के रूप में भर्ती, दस लाख रुपए तक का बीमा एवं ईपीएफओ की सुविधा प्रदान करने जैसी मांगों को लेकर किया है। प्रदर्शन के बाद यह शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय में ज्ञापन देने भी जाएंगे। बता दें कि कई तरह के नारों के बीच सैकड़ों शिक्षक प्रदेश भर से इस प्रदर्शन के लिए भोपाल पहुंचे।

कुएं का गंदा पानी पीया..2 की मौत, 20 बीमार

छिंदवाड़ा में अब भी खुला पड़ा कुआं; अस्पताल में जमीन पर लिटाए मरीज

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के चिमटीपुर गांव में दूषित पानी पीने से 8 दिन में महिला और ढाई साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत है। इससे प्रशासन में हड़कंप है। जिस कुएं का दूषित पानी पीने से ऐसे हालात बने हैं, वह आज भी खुला है।

आदिवासी बाहुल्य चिमटीपुर गांव में 261 लोगों की आबादी है। मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर चलना होता है। पूरी सड़क कच्ची है। गांव में कोई बीमार होता है, तो अंदर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। मरीज को मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। बारिश के दिनों में घाट वाले क्षेत्र में पहाड़ की मिट्टी सड़क पर बहकर आ जाती है। ऐसे में कीचड़ हो जाता है।

सबसे पहले ढाई साल की बच्ची की मौत हुई- 18 जुलाई को ढाई साल की परीजा बिसन लाल की मौत हुई। दो दिन बाद यानी 20 जुलाई को गांव में भूरा सिंह उइके (50) और उसकी पत्नी अतरवती उइके (42) को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई। 21 जुलाई को एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो निजी वाहन से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अतरवती ने दम तोड़ दिया। अतरवती की बेटी वंदना (6) और मिलन (3) को तामिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद लगातार गांव में एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। भूरा

लाल उइके ने बताया, 'मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, तो दो हजार रुपए खर्च कर निजी गाड़ी से अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी मौत हो गई। हम लोग जिस कुएं का पानी पी रहे हैं, उसके ऊपर गंदगी है। भूरा सिंह ने बताया, 'मेरी पत्नी अतरवती को पेट दर्द और उल्टी- दस्त की शिकायत हुई। 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। प्राइवेट गाड़ी से उसे अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में पत्नी का निधन हो गया।

महिला की मौत के बाद हरकत में प्रशासन- अतरवती की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। गांव में डोर टू डोर सर्वे किया। इनमें से 20 लोग डायरिया से पीड़ित मिले। इनमें से 13 लोगों का तामिया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, गंभीर 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी का घर पर इलाज किया जा रहा है। गांव में स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है। मंगलवार को सीएमएचओ एनके शास्त्री भी गांव पहुंचे। उन्होंने टीम को मरीजों की जांच के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की बात कही। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। इस कारण मरीजों को जमीन पर भर्ती करना पड़ा।

48 बेड वाले मेल वार्ड में 80 से ज्यादा पेशेंट- छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत ये है कि 48 बिस्तरों वाले वार्ड में 80 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। ऐसे में जमीन पर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मथेलाल उइके (60) की हालत भी गंभीर है। मथेलाल के बेटे राकेश उइके ने बताया, 'दूषित पानी पीने की वजह से पिता की तबीयत बिगड़ी थी।

कुएं का गंदा पानी पीने से बिगड़ी तबीयत

गांव में पहाड़ियों के नजदीक सरकारी कुआं है। इसी कुएं का पानी सभी गांववाले पीते हैं। बारिश के दिनों में कुएं में आसपास का गंदा पानी आ जाता है। इससे पानी दूषित हो गया है। इसी कुएं का पानी पीने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि, प्रशासन ने फिलहाल इस कुएं से पानी पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएचई की टीम ने पानी का सैंपल भी लिया है। गांव में स्थित आदिवासी हॉस्टल से वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था की गई है।

आठ दिन बाद भी कुआं बंद नहीं किया

मीडिया की टीम जब गांव पहुंची, तब कुएं का पानी हरा दिख रहा था। इसके आसपास और कुएं में गंदगी भी थी। दरअसल, पहाड़ी पर होने के कारण कुएं में गंदगी बहकर आ जाती है। भले ही प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया हो, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया है। यानी अब तक कुआं खुला पड़ा है।

गांव की रहने वाली अमरवती ने बताया, कुएं का पानी पीते हैं, जिसमें बारिश की गंदगी है। अब साहब लोगों ने यहां का पानी पीने से मना कर दिया है। दूसरी जगह से पानी दे रहे हैं। मेरी भी 20 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। कल बॉटल लगी है। अभी ठीक हूं।

जिम्मेदार क्या कहते हैं

तामिया के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. जितेंद्र उइके ने बताया कि चिमटीपुर में डायरिया की वजह से स्थिति गंभीर हो गई थी। एक महिला की मौत भी हो गई। महिला को कैंप से रेफर करते समय मौत हो गई थी।

ससुराल से पहली बार मायके आई नवविवाहिता के साथ रेप

पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची, वीएचपी ने विरोध-प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र में शादी के बाद पहली बार मायके आई 20 वर्षीय नव-विवाहिता के साथ गांव के रहने वाले एक युवक ने रेप किया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत रन्नौद थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके बाद नाराज होकर पीड़िता के परिवजन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे। जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 9 जुलाई को हुई थी। इससे पहले 4 जुलाई को गांव के ही रहने वाले सलमान खान ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया था। शादी की तारीख नजदीक होने के चलते उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। 9 जुलाई को वह शादी कर अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। 16 जुलाई को अपने भाई के साथ अपनी ससुराल से मायके आ गई थी। 17 जुलाई की सुबह 10 बजे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान उसे अकेला देख सलमान पठान उसे खींचकर पड़ोस के एक बाड़े में ले गया था।

पीछे-पीछे लाओ, भारी बारिश के चलते कटनी में जब ट्रेन को भी दिखाना पड़ा रास्ता

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश कटनी में एक अनोखा मामला सामने आया है। भारी बारिश के कारण रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। पटरियां नहीं दिखने के कारण एक ड्राइवर को ट्रेन चलाने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में रेलवे के कर्मचारियों ने एक तरकीब निकाली।

रेलवे के कर्मचारी पटरियों के बीच में आगे-आगे चलने लगे और ड्राइवर से ट्रेन लेकर पीछे-पीछे आने को कहा। उनके द्वारा रास्ता दिखाए जाने के बाद उनके पीछे बढ़ती इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मिनट छह सेकंड के इस वीडियो में यह साफ देखा सकता है कि किस तरह रेलवे के कर्मचारी आगे-आगे चल रहे हैं और ड्राइवर ट्रेन लेकर उनके पीछे-पीछे आ रहा है।

इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और आप हैं कि नेहरू के समय की इन ट्रेनों का जिक्र कर रहे हैं। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि इस ट्रेन के लोको पायलट को मुंबई लोकल ट्रेन के लोको पायलट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आखिर इतनी क्या जरूरी थी कि पानी में ट्रेन चलानी पड़ रही है। अगर ट्रेन बेपटरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता।

बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटे से झामझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 4 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश के डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और नीमच जिलों में बारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में 28 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।